page 1 and 8 July 23_page 1 Mar 25 final ds.qxd 7/23/2026 1:57 AM Page 1

epaper.dehatsandesh.com

3 चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंचा

5 विश्व कप जीतकर 51 साल का इंतजार खत्म करना चाहते हैं: हरमनप्रीत

8 कठुआ में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक, 22 मामलों की समीक्षा

न्यूनतम 22

मौसम जम्मू

अधिकतम 25

E-mail: dehatsandesh@gmail.com

जम्मू-कश्मीर का एकमात्र ग्रामीण दैनिक

देहात संदेश

वर्ष-23, जम्मू तवी, अंक-184 | जम्मू तवी, वीरवार 23 जुलाई, 2026 | मूल्य-3 रूपये- (लेह) 4 रूपये | पृष्ठ -8

सचिवों से बोले मोदी, सभी सुधारों के केन्द्र में नागरिकों का कल्याण होना चाहिए : मोदी

नयी दिल्ली ,22 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को यहां अपने आवास पर विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक में विकसित भारत के लक्ष्यों को पाने की दिशा में प्रगति की समीक्षा की और जोर देकर कहा कि सभी सुधारों के केन्द्र में नागरिकों का कल्याण होना चाहिए।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि बैठक में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबंधित क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने बैठक में इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी सुधारों के केंद्र में नागरिकों का कल्याण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए सुधारों को असल रफ़्तार मिलनी चाहिए और उनसे सार्थक बदलाव आने चाहिए। उन्होंने कहा कि सुधारों का मकसद सिर्फ़ सरकार के कामकाज को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने के सफ़र को तेज़ करना है। उन्होंने कहा कि शासन प्रणाली में तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। उन्होंने बदलते माहौल की ज़रूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए शासन प्रक्रियाओं को अपनाने और मज़बूत करने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों में उभरती ज़रूरतों की व्यापक मैपिंग करने का सुझाव दिया।

श्री मोदी ने देश के विकास लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी सरकार के मिलकर काम करने के नज़रिए की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनाने का सपना एक जन आंदोलन बनना चाहिए और भारत के युवा इस विज़न की नींव बनने चाहिए।

प्रधानमंत्री ने युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने सुझाव दिया कि विभागों के बीच अलग-थलग रहकर काम करने की संस्कृति को खत्म करने और युवाओं पर केंद्रित पहलों में विभागों के बीच बेहतर तालमेल और एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत तंत्र विकसित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

श्री मोदी ने खेलों के विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि खेल पर्यटन के एक प्रमुख फोकस क्षेत्र के रूप में उभरने के साथ, भारत को खुद को एक वैश्विक खेल हब के रूप में स्थापित करने के लिए बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेज़बानी करने का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने खेल क्षेत्र में स्टार्टअप के माध्यम से प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के महत्व पर ज़ोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों द्वारा पीएम कुसुम योजना जैसी पहलों को बड़े पैमाने पर अपनाने से कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अवसरों और भविष्य की ज़रूरतों के साथ बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए कौशल की ज़रूरतों की ग्लोबल मैपिंग की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। सचिवों ने अपने-अपने क्षेत्रों में विभिन्न पहलों और चुनौतियों पर अपने अनुभव और विचार साझा किए।

आवश्यक सेवाओं की समयबद्ध बहाली, प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत और स्थिति पर लगातार निगरानी के दिए निर्देश

लगातार बारिश के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राहत और बहाली कार्यों की समीक्षा तेज की

श्रीनगर, 22 जुलाई। लगातार हो रही बारिश और अचानक आई बाढ़ (फ्लैश फ्लड) के मद्देनज़र मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को यहां सिविल सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में जम्मू-कश्मीर में राहत एवं बचाव कार्यों, आवश्यक सेवाओं की बहाली तथा समग्र बाढ़ तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्री सकीना इत्तू, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, प्रशासनिक सचिव, संभागीय आयुक्त कश्मीर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा, युवा सेवा एवं खेल, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा एआरआई एवं प्रशिक्षण मंत्री सतीश शर्मा, संभागीय आयुक्त जम्मू तथा सभी उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनियमित मौसम के कारण उत्पन्न बाढ़ जैसी परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उच्च स्तर की तैयारियां बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बार-बार सामने आ रही बाढ़ जैसी स्थितियां दीर्घकालिक बाढ़ शमन उपायों और मजबूत आधारभूत ढांचे की मांग करती हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को जान-माल के नुकसान को न्यूनतम करने, विशेष रूप से पेयजल और बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं को 24 घंटे के भीतर बहाल करने, संवेदनशील क्षेत्रों को प्राथमिकता देने तथा लापता लोगों की तलाश और बरामदगी के प्रयास तेज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जम्मू और कश्मीर के संभागीय आयुक्तों को तत्काल बाढ़ की स्थिति का आकलन कर सबसे अधिक प्रभावित जिलों की पहचान करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2025-26 की तर्ज पर इन जिलों के उपायुक्तों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए ताकि राहत, पुनर्वास और क्षतिग्रस्त आधारभूत ढांचे की बहाली का कार्य तुरंत शुरू किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने पूंछ और राजौरी जिलों में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि सभी राहत शिविरों में प्रभावित लोगों के लिए पर्याप्त भोजन, स्वच्छ पेयजल और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

खबर संक्षेप

बांदीपोरा में अचानक आई बाढ़- लापता लड़का मृत मिला, माँ की तलाश जारी

बांदीपोरा, 22 जुलाई उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले में अचानक आई बाढ़ में अपनी माँ के साथ बह गए 14 साल के लड़के का शव बुधवार को मिला जबकि लापता महिला की तलाश जारी है। अधिकारियों ने बताया कि लड़के का शव गुज़रबल इलाके के एक नाले से बरामद किया गया और कानूनी औपचारिकताओं के लिए बांदीपोरा ज़िला अस्पताल ले जाया गया। मृतक की पहचान बाद में अमीर खटाना (14) के रूप में हुई जो स्वर्गीय महबूब खटाना का बेटा और बोनिबल तंगथ का निवासी था। अधिकारियों ने बताया कि ज़िले के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ के बाद अमीर और उसकी माँ गुडी बेगम तेज़ बहाव वाले पानी में बह गए थे। वे नाले में बहकर आ रही जलाऊ लकड़ी को निकालने की कोशिश कर रहे थे। बांदीपोरा के तहसीलदार फिरदौस अहमद ने बताया कि गुडी बेगम अभी भी लापता है और उसे खोजने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है

आतंकी हमले के बाद कश्मीर में 1,000 से ज्यादा ओजीडब्लू हिरासत में लिए गए

अनंतनाग, 22 जुलाई । दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में बुधवार को आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत के बाद सुरक्षाबलों ने कश्मीर घाटी भर से 1,000 से ज़्यादा ओवर ग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्लू) को हिरासत में लिया है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन की आज दोपहर करीब 12:30 बजे अनंतनाग के लाल चौक पर एक आतंकवादी ने गोली मारकर हत्या कर दी। हमले के बाद सुरक्षाबलों ने हमलावर का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया और पूरे अनंतनाग शहर की घेराबंदी कर दी। हमले के बाद सुरक्षाबलों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर पूरी घाटी में छापेमारी शुरू की। उन्होंने कहा कि छापेमारी के दौरान 1,000 से ज़्यादा ओजीडब्लू (आतंकी सहयोगी) को हिरासत में लिया गया है। साथ ही अनंतनाग ज़िले सहित कई जगहों पर तलाशी अभियान तेज़ कर दिए गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हमले की निंदा करते हुए इसे कायरतापूर्ण हरकत बताया और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात और आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी ने खुद घटनास्थल का दौरा किया और सुरक्षा स्थिति का जायज़ा लिया।

भारी बारिश के कारण जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर यातायात रुका

रामबन, 22 जुलाई। बुधवार को जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। पूरे रास्ते में हुई भारी बारिश के कारण उधमपुर और रामबन जिलों में कई जगहों पर पत्थर गिरने और मिट्टी धंसने (मडस्लाइड) की घटनाएं हुईं। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए एहतियात के तौर पर जम्मू और श्रीनगर दोनों तरफ से यातायात रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि उधमपुर और रामबन जिलों के संवेदनशील इलाकों में मिट्टी धंसने और पत्थर गिरने की कई घटनाएं हुईं जिससे हाईवे गाड़ियों की आवाजाही के लिए असुरक्षित हो गया।

अनंतनाग आतंकी हमला करने वालों को सज़ा ज़रूर मिलेगी : मनोज सिन्हा

श्रीनगर, 22 जुलाई । जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को अनंतनाग ज़िले में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की हत्या की निंदा की और कहा कि इस घिनौनी हरकत के लिए सज़ा ज़रूर मिलेगी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन की अनंतनाग के लाल चौक पर दोपहर करीब 12:30 बजे एक आतंकवादी ने गोली मारकर हत्या कर दी। सिन्हा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मैं इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। इस घिनौनी हरकत के लिए सज़ा ज़रूर मिलेगी। पुलिस और हमारे सुरक्षा बल मौके पर मौजूद हैं और दोषियों को सज़ा दिलाएँगे। उन्होंने आगे कहा कि मैंने अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद स्थिति की समीक्षा करने के लिए डीजीपी नलिन प्रभात से बात की। ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ। पूरा देश शहीद के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है।डीजीपी नलिन प्रभात ने स्थिति का खुद जायज़ा लेने के लिए घटनास्थल का दौरा किया आतंकवादी का पता लगाने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है।

अनंतनाग में आतंकी हमला, एक पुलिसकर्मी शहीद

अनंतनाग, 22 जुलाई । जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में बुधवार को अनंतनाग शहर में आतंकवादियों के हमले में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया। लश्कर-ए-तैयबा के एक सहयोगी संगठन, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए हमले की ज़िम्मेदारी ली है। अधिकारियों ने बताया कि अनंतनाग के लाल चौक पर गोलीबारी दोपहर करीब 12:30 बजे हुई। उन्होंने बताया कि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन हमले में घायल हो गए और उन्हें अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने हुसैन को मृत घोषित कर दिया। सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और हमलावरों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

उमर ने अनंतनाग आतंकी हमले की निंदा की, शहीद पुलिसकर्मी के बलिदान को बताया सर्वोच्च

श्रीनगर, 22 जुलाई । मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुए आतंकी हमले की निंदा की, जिसमें इंडिया रिजर्व पुलिस की तीसरी बटालियन के हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पुलिसकर्मी की मौत से बहुत दुखी हैं और उन्होंने उनकी मौत को ड्यूटी के दौरान दिया गया सर्वोच्च बलिदान बताया।

रामबन जिले के रामसू में टैम्पो पर पत्थर गिरने से 2 लोगों की मौत, कई घायल

रामबन, 22 जुलाई । रामबन जिले के रामसू के पास बुधवार को जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक यात्री टैम्पो पर ऊपर से पत्थर गिरने से दो लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। लगातार हो रही बारिश के बीच टैम्पो पर पत्थर गिरने से गाड़ी को काफ़ी नुकसान पहुंचा। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में कई यात्री घायल हो गए, जिन्हें तुरंत बचाया गया और रामसू के प्राइमरी हेल्थ सेंटर और आस-पास के अन्य अस्पतालों में ले जाया गया। बाद में घायलों में से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि बाकी घायलों की हालत पर नज़र रखी जा रही है। पुलिस और स्थानीय स्वयंसेवकों की मदद से बचाव दलों ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया। मृतकों की पहचान की जा रही है।

रियासी के महोर में भारी बारिश से तीन घर क्षतिग्रस्त

रियासी, 22 जुलाई। बुधवार को रियासी ज़िले के महोर इलाके में बारिश से जुड़ी एक घटना में तीन रिहायशी घर क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकारियों ने बताया कि घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए जिससे राशन, बिस्तर, बर्तन और कपड़ों सहित घर का सामान नष्ट हो गया।

उन्होंने कहा कि इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है। क्षतिग्रस्त घर महोर के शिकारी गाँव के निवासी जदेश सिंह, ब्रंधिर सिंह और लाल सिंह के हैं। नुकसान के सटीक कारण और नुकसान की सीमा का आकलन किया जा रहा है।

ड्यूटी के दौरान फिसलने से जवान की मौत

राजौरी, 22 जुलाई। राजौरी ज़िले के सुंदरबनी सेक्टर में एक फॉरवर्ड पोस्ट पर ड्यूटी के दौरान फिसलने से सेना के एक जवान की मौत हो गई। यह घटना मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को हुई। एक अधिकारी ने बताया कि मृतक जो 19 जम्मू-कश्मीर राइफल्स का राइफलमैन था और फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात था। उन्होंने बताया कि पोस्ट पर ड्यूटी के दौरान फिसलने के कारण राइफलमैन को गंभीर चोटें आईं और ड्यूटी के दौरान ही उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान पंजाब के रहने वाले राइफलमैन सुखप्रीत सिंह के तौर पर हुई है। अधिकारी ने कहा कि घटना का संज्ञान ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता भारत और चीन के बीच सामान्य संबंधों की पहली शर्त : जयशंकर

नयी दिल्ली 22 जुलाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता को दोनों देशों के बीच सामान्य संबंधों की पहली शर्त करार देते हुए कहा है कि इस पर ध्यान दिये जाने तथा संबंधित तंत्रों को इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किये जाने की जरूरत है।श्री जयशंकर ने बुधवार को क्वाड और आसियान देशों की बैठकों से इतर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कजान और तियानजिन की मुलाकातों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनके बाद से भारत और चीन के बीच संबंध धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं। भारत और चीन के बीच स्थिर और परस्पर सहयोग पर आधारित संबंधों को बहु- ध्रुवीय एशिया और बहु-ध्रुवीय दुनिया के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा, फ़हमारा मानना है कि आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी संवेदनशीलता के आधार पर ही स्थिर और सहयोगात्मक संबंध विकसित किया जा सकता है। ऐसा संबंध बहु-ध्रुवीय एशिया और बहु-ध्रुवीय दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

मुख्य सचिव ने भव्य योजना की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की

औद्योगिक पार्कों की स्थापना, कार्यान्वयन और दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए प्रस्तावित तंत्र पर विचार-विमर्श किया

श्रीनगर, 22 जुलाई। मुख्य सचिव अटल दुल्लू ने आज भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्या) की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। यह भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश भर में अगली पीढ़ी के प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करना और जम्मू-कश्मीर को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस), पी.डी.डी, एसीएस, वित्त, आयुक्त सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, प्रबंध निदेशक, एसआईडीसीओ और संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रस्तावों की विस्तृत समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने श्रीनगर के पेखरी, सांबा और नौगाम में प्रस्तावित प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्कों के लिए तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का आकलन किया। विस्तृत योजना और तकनीकी सुदृढ़ता की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि भव्य योजना के तहत भारत सरकार को प्रस्तुत करने से पहले विद्युत विकास विभाग और लोक निर्माण (आर एंड बी) विभाग द्वारा डीपीआर की पूरी तरह से जांच की जाए ताकि उनकी तकनीकी व्यवहार्यता, इंजीनियरिंग सुदृढ़ता और निर्धारित मानकों के अनुरूपता सुनिश्चित हो सके। मुख्य सचिव ने प्रस्तावित औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए चिन्हित भूमि की स्थिति की भी समीक्षा की और लागू कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी के पक्ष में भूमि के हस्तांतरण और निहित होने की प्रक्रिया के संबंध में विवरण मांगा।

उपमुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित बेला का दौरा कर राजौरी में बहाली कार्यों की समीक्षा की

राजौरी, 22 जुलाई। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने आज राजौरी जिले के बाढ़ प्रभावित बेला क्षेत्र का दौरा कर हाल ही में आई फ्लैश फ्लड के बाद जमीनी स्थिति का जायजा लिया। दौरे के दौरान उपमुख्यमंत्री ने मौके पर तैनात अधिकारियों एवं फील्ड कर्मचारियों से बातचीत की। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत, मलबा हटाने तथा आवश्यक सेवाओं की जल्द बहाली के निर्देश दिए ताकि सामान्य जनजीवन जल्द से जल्द पटरी पर लौट सके। इसके बाद उपमुख्यमंत्री ने राजौरी में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर फ्लैश फ्लड के बाद चल रहे बहाली कार्यों और आपातकालीन राहत उपायों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों की तैयारियों और कार्रवाई का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक सेवाओं की शीघ्र बहाली तथा प्रभावित लोगों तक प्रभावी राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जिला प्रशासन और सभी संबंधित विभाग युद्धस्तर पर राहत, बचाव और बहाली कार्यों में जुटे हुए हैं। फ्लैश फ्लड की घटना में प्रारंभिक तौर पर चार लोगों के लापता होने की सूचना मिली थी, जिनमें से तीन के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि एक अन्य लापता व्यक्ति की तलाश जारी है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), पुलिस, भारतीय सेना तथा अन्य एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से बचाव अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन प्रभावित लोगों की सुरक्षा और राहत के लिए चौबीसों घंटे कार्य कर रहा है। आधारभूत ढांचे की बहाली की समीक्षा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को राष्ट्रीय राजमार्ग-144ए पर समुचित जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा जहां कार्य की प्रगति धीमी है वहां सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की क्षति से बचने के लिए वैज्ञानिक तरीके से जल निकासी व्यवस्था विकसित करना आवश्यक है। बैठक में बताया गया कि फ्लैश फ्लड के कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की 157 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। उपमुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई और बीआरओ के अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर सड़क संपर्क बहाल करने तथा सभी क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसंपत्तियों की शीघ्र मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जल शक्ति विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि 131 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। सामान्य जलापूर्ति बहाल होने तक प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। बैठक में यह भी बताया गया कि प्रभावित 150 बिजली फीडरों में से 120 बहाल किए जा चुके हैं, जबकि शेष 30 फीडरों को भी शाम तक चालू कर दिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को कालाबाजारी तथा जमाखोरी पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि फंसे हुए मजदूरों और कमजोर वर्गों के परिवारों तक राशन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

चौथे दिन भी शुरू नहीं हो सकी अमरनाथ और वैष्णोदेवी की यात्रा

जम्मू, 22 जुलाई । जम्मू-कश्मीर में खराब मौसम की वजह से श्री अमरनाथ जी यात्रा, माता वैष्णो देवी यात्रा, शिव खोड़ी यात्रा और मचैल माता यात्रा चौथे दिन भी शुरू नहीं हो सकी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के खराब मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए प्रशासन ने शनिवार शाम को ही इन यात्रों को रोक दिया था।

मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में बालटाल और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में नंदीवान-पहलगाम के दो रास्तों से होने वाली अमरनाथ यात्रा 18 जुलाई की शाम को रोक दी गई थी। इसके साथ ही कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर, रियासी में शिव खोड़ी मंदिर और किश्तवाड़ में मचैल माता मंदिर की यात्रा भी उसी दिन रोक दी गई थी। हालांकि पहलगाम रास्ते पर गुफा मंदिर के लिए आखिरी पड़ाव पंचतरणी और बालटाल बेस कैंप में फंसे तीर्थयात्रियों को क्रमशः 19 और 20 जुलाई को दर्शन के लिए जाने की अनुमति दी गई ।

साभार : अशोक कुमार मुनड़ेतिया

कैसे हटाएं मेकअप

अगर मेकअप न हटाया जाए तो वह त्वचा के छिद्र को बंद कर देता है और मेकअप में मौजूद केमिकल त्वचा को क्षति पहुंचाते हैं। इसलिए सोने से पहले अपना मेकअप उतारना न भूलें। आपकी मेकअप किट में अच्छी क्वॉलिटी का मेकअप रिमूवर होना बहुत जरूरी है। आंखें काफी सेंसिटिव होती हैं और उन्हें अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है। फेशियल मेकअप जैसे फाउंडेशन और लिपस्टिक, वॉटर बेस्ट मेकअप क्लींजर से आसानी से साफ हो जाते हैं, लेकिन आई मेकअप जैसे-लाइनर, काजल और मस्कारा को हटाने के लिए अलग रिमूवर की जरूरत होती है। इसके लिए मेकअप रिमूवर सलूशन में अधिक ऑयल की जरूरत होती है।

आई मेकअप रिमूवर

यह फेशियल मेकअप रिमूवर से अधिक मृदु होता है। इसके लिए बेबी ऑयल और बेबी लोशन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप मेकअप का प्रयोग नहीं करती हैं तब भी त्वचा को नियमित रूप से माइल्ड क्लींजर

से साफ करना जरूरी है। ताकि धूल-मिट्टी व गंदगी साफहो जाए। ऐसा करने से त्वचा में किसी प्रकार की जलन, एक्ने और पिंपल्स नहीं होने पाते।

1. आंखों का मेकअप हटाने के लिए हाथ साफ होने चाहिए। लाइनर और मस्कारा हटाते समय हलके हाथों से साफ करें।

2. आई मेकअप हटाने के लिए होममेड क्लींजर इस प्रकार बनाएं- कैस्टर ऑयल+ऑलिव ऑयल+कैनोला ऑयल की बराबर मात्रा लेकर एक साथ मिलाएं फिर टिश्यू पेपर या कॉटन बॉल में थोड़ा सा मिश्रण लेकर आंखों को साफ करें।

मेकअप रिमूवर

1. मेकअप हटाने के लिए जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें उसे कॉटन बॉल की सहायता से ही करें। चेहरे और गर्दन को थपथपाते हुए साफ करें। अगर एक बार ऐसा करने से मेकअप साफ न हो तो दोबारा कॉटन बॉल गीला करके चेहरा साफ करें।

2. आप चाहें तो घर पर एक अच्छा इंस्टैंट मेकअप रिमूवर बना सकती हैं, जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। 2 चम्मच गुलाबजल में कुछ बूंदें बेबी ऑयल और 3-4 बूंद नीबू का रस मिलाएं। इस मिश्रण को कॉटन बॉल में लगाकर चेहरा साफ करें। यह छिद्र को साफ करता है, मेकअप को अच्छी तरह हटाता और त्वचा की धूल-गंदगी भी बारीकी से साफ कर देता है।

3. ताजे दूध में थोड़ा सा नीबू का रस मिलाकर क्लींजर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यह चेहरा साफ जरूर करता है, लेकिन ऑयली स्किन के लिए अच्छा उपाय नहीं है। ऑयली स्किन के लिए इसमें थोड़ा दही का पानी भी मिलाया जा सकता है।

4. बाजार में बहुत तरह के क्लींजर, मेकअप रिमूवर उपलब्ध हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, उसमें एल्कोहॉल न हों। एल्कोहॉल त्वचा के लिए नुकसानदेह होता है। यह फ्रेश लुक देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद त्वचा को रुखा बना देते हैं।

5. मेकअप हटाने के बाद त्वचा को टोन अप करने के लिए टोनर लगाएं। उसके बाद मॉयस्चराइजर लगाएं, ताकि त्वचा की कुदरती नमी बरकरार रहे। नियमित क्लीनिंग, टोनिंग और मॉयस्चराइजिंग से त्वचा किसी भी प्रकार की समस्या से दूर रहती है और लंबे समय तक स्वस्थ रहती है। इसे अपना रुटीन बना लें ताकि त्वचा ताउम्र जवां और स्वस्थ बनी रहे।

अब डैंड्रफ रहे काबू में

बारिश के मौसम में उमस और पसीने से बालों में चिपचिपाहट हो जाती है। रूसी एक प्रकार की निर्जीव त्वचा है, जो बालों की जड़ों के आसपास जमा हो जाती है। इसलिए अपने बालों को साफ रखें और महीन दांतों वाली कंघी का प्रयोग करे। ताकि सिर की त्वचा से आसानी से रूसी बाहर निकल जाए। यहां हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब बता रहे है, उपयोगी टिप्स।

1. बालों में प्रतिदिन ब्रश करने और मालिश करने से डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि इन उपचारों से रक्तसंचार तीव्र गति से होता है और मृत त्वचा निकल जाती है।

2. गर्म ऑलिव ऑयल में कुछ बूंदें अदरक के रस की डालकर इससे सिर पर कुछ देर मालिश करे। आधे घंटे तक बालों में लगा रहने के बाद शैंपू कर लें।

3. बालों में रूसी होने से बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। ऐसे में प्याज का रस लगाएं। आधा घंटे बाद एक मग में नीबू की कुछ बूंदें डाल कर उस पानी से धोएं।

4. नीम की पत्तियों का रस नीबू के रस में मिलाकर सिर में लगभग तीस मिनट तक लगाएं। फिर शैंपू कर लें या फिर शैंपू करने के बाद सिरके और नीबू का रस बराबर मात्रा में लेकर 5-10 मिनट तक के लिए सिर में लगा रहने दें। उसके बाद बालों को धो लें।

5. जोजोबा ऑयल और कोकोनट ऑयल को मिलाकर उंगली के पोरों से धीरे-धीरे सिर की त्वचा पर मालिश करे। इसके बाद गर्म पानी में भीगे तौलिये को निचोड़कर थोड़ी देर तक सिर पर लपेटकर रखें। आधे घंटे बाद शैंपू करे।

जंब चुनें शैंपू

1. जिस शैंपू से ज्यादा झाग न निकले उसे फेंकें नहीं, क्योंकि बालों की अच्छी सफाई के लिए यह जरूरी नहीं है कि शैंपू से खूब सारा झाग निकले। सुगंध वाले शैंपू इस्तेमाल करना भी कोई जरूरी नहीं है। ऐसा शैंपू चुनें, जो आपके बालों की किस्म के मुताबिक हो और बालों को सूट भी करे।

2. अगर बाल पतले और रूखे या सामान्य है तो ऐसा शैंपू प्रयोग करे जो बालों को वॉल्यूम दें, बाउंस करे और संवारने में आसान बनाए।

3. शैंपू के लेबल पर ध्यान दें अगर उसमें एक्स्ट्रा बॉडी शैंपू छपा है तो यह फॉर्मूला बालों पर एक परत बना देगा जिससे बालों को बॉडी मिलेगी और वे घने नज़र आएंगे। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि एक अच्छे ब्रैंड का शैंपू इस्तेमाल करे।

4. अगर बाल बेहद रूखे है तो ड्राई एंड डैमेज हेयर के लिए बना शैंपू इस्तेमाल करे। यह बालों के लिए जरूरी आर्द्रता के संतुलन को बनाए रखता है और सूर्य की तेज अल्ट्रावॉयलेट किरणों के दुष्प्रभाव से भी बालों को बचाता है।

5. अगर आपने अभी-अभी हेयर कलर कराया है और उसकी चमक को बरकरार रखना चाहती है तो ऐसा शैंपू इस्तेमाल करे जिसमें अल्ट्रावॉयलेट फ़िल्टर्स हों और माइल्ड क्लींज़िंग भी करे, ताकि आपके बालों को अल्ट्रावॉयलेट किरणों से नुकसान न पहंचे।

6. अगर आप बहुत सारे स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती है तो आपको क्लैरीफ़ाइंग शैंपू का प्रयोग करना चाहिए, जो आपके बालों की डीप क्लींज़िंग करता है और स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किए गए केमिकल के असर को भी कम करता है।

7. अगर आप स्विमिंग करती है तो डीटॉक्सीफाइंग शैंपू का इस्तेमाल करे जो क्लोरीन और कॉपरयुक्त पानी के प्रभाव को दूर कर देता है।

व्यक्तित्व मे निखार लाएं मोती जैसे दांत

दांत खाना खाने के लिए तो जरूरी है ही, मोहक, प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। कुछ लोग यूं तो बहुत खूबसूरत होते है, लेकिन मुंह खोलते ही उनका आकर्षण खत्म हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ मनाली के साथ। उसके हाथ से मॉडलिंग का अवसर सिर्फ इसलिए छूट गया, क्योंकि उसके दांत छोटे-बड़े है और पीले भी पड़ गए है। ऐसा कुछ आपके साथ न हो, इसलिए शुरू से ही दांतों की उचित देखभाल जरूरी है।

ध्यान दें शुरु से

दंत चिकित्सक डॉ.ज्योति कपाड़िया के अनुसार जब बच्चों के दांत उग आएं, तभी से सुबह व रात में सोते समय ब्रश की आदत डाल देनी चाहिए। खाते समय भोजन के कण दांतों के बीच फंस जाते है, जो ब्रश करने से निकल जाते है। यदि इन्हे न निकाला जाए तो ये सड़ने लगते है, जिससे दांतों में सड़न और कैविटी पैदा हो जाती है। इस कारण दांतों में तेज दर्द हो सकता है व असमय दांत टूट सकते है। लोग सोचते है दूध केदांत तो टूट जाते है। इतनी देखभाल क्यों करे? दूध के सभी दांत एक साथ नहीं टूटते। एक-एककर टूटते जाते है और उनकी जगह नए दांत आते-जाते है। अगर कोई पुराना सड़ा हुआ हो तो वह नए दांत को भी सड़ा सकता है।

जरूरी है दांतों की सफाई

बच्चों को टॉफियां खास तौर से पसंद होती है। ध्यान रखें कि कुछ भी मीठा खाने के बाद बच्चे कुल्ला जरूर करे। कुछ लोग समझते है कि टूथपेस्ट का अधिक इस्तेमाल करने से दांत ठीक से साफ होते है। ऐसा नहीं है, बल्कि अधिक टूथपेस्ट दांतों की ऊपरी सुरक्षा परत इनामेल को नुकसान पहुंचा सकता है। सामान्यतया ऐसे टूथपेस्ट का उपयोग करना चाहिए जिसमें फ्लोरीन हो। फ्लोरीन हड्डियों में पाया जाने वाला एक तत्व है। यह दांतों को मजबूत बनाता है। लेकिन ज्यादा फ्लोरीन भी दांतों को पीला और खराब कर सकता है। इस बीमारी को फ्लोरोसिस कहते है। जिस क्षेत्र के पानी में फ्लोरीन की मात्रा अधिक हो, वहां के लोगों को फ्लोरीन वाले टूथपेस्ट से बचना चाहिए।

विटमिंस का करे भरपूर उपयोग

दांतों के साथ मसूड़ों की देखभाल भी जरूरी है। ब्रश के बाद मसूड़ों की उंगलियों से हलकी -हलकी मालिश करें। कुछ बीमारियों के बाद मसूड़े ढीले पड़ जाते है और दांत हिलने लगते है। कभी-कभी मसूड़ों में छाले भी पड़ जाते है। ऐसे में भोजन में नमक-मिर्च आदि का उपयोग कम करे, क्योंकि उनसे जलन होती है। साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि दांतों पर कोई आघात न पहुंचे क्योंकि उस समय ये टूट सकते है। खाने में विटमिन बी कॉम्प्लेक्स व विटमिन सी का भरपूर प्रयोग करे और डॉक्टर की सलाह का पालन करे ताकि आपके मसूड़े जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। विटमिन सी आंवला, संतरा, मौसमी, टमाटर, साग-सब्जियों में मिलता है। इसका नियमित सेवन आपको स्कर्वी और पायरिया से दूर रखेगा। पायरिया मसूड़ों की बीमारी है जो एंट अमीबा जिंजिवेलिस नाम के कीटाणु से होती है। इसमें मुंह से दुर्गंध तथा मसूड़ों से खून आने की शिकायत होती है। पायरिया होने पर डॉक्टर के परामर्श का पालन करे। दवाओं के साथ-साथ हाइड्रोजन-पर-ऑक्साइड से कुल्ला करना भी लाभदायक हो सकता है।

दूर करे कैविटी

डॉ.ज्योति के अनुसार यह दांत अगर सड़ जाएं और उसमें कैविटी बनने लगे तो कैविटी को भरवाया जा सकता है। इससे पहले दांत को अच्छी तरह से साफ व कीटाणुमुक्त करना पड़ता है। ताकि कैविटी भरने के बाद अंदर कोई कीटाणु न रह जाए और दांत को फिर से सड़ने से बचाया जा सके। ज्यादा सड़े या जड़ों से कमजोर दांतों को निकलवाकर उनकी जगह नकली दांत या नए दांतों का सेट लगवाया जा सकता है।

दांतों का सौंदर्य बढ़ाएं

दांत पीले पड़ गए हों या दो दांतों के बीच अधिक दूरी हो, दांत छोटे-बड़े या बाहर की ओर निकले हों तो इससे भी चेहरे के सौंदर्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसे में डेंटिस्ट से अवश्य मिलें। डेंटिस्ट की सलाह पर पीले दांतों की सफाई करवाएं। बाहर की ओर निकले या दूरी वाले दांतों पर कुछ दिनों के लिए क्लिप लगवाएं। बड़े दांतों को घिसवा सकती है। छोटे दांतों में नीचे से दांतों जैसा दिखने वाला पदार्थ जोड़कर उन्हे समान आकार का बनवाया जा सकता है।

आकर्षक मुसकान के लिए

ग्रूमिंग एक्सपर्ट और सौंदर्य विशेषज्ञा डॉ.ब्लॉसम कोचर के मुताबिक, %आपके चेहरे की कंप्लीट स्माइल मेकओवर भी की जा सकती है। इसमें आपके चेहरे के आकार को देखकर ये आकलन किया जाता है कि इस पर कैसी मुसकान और दांत अच्छे लगेंगे। फिर उसके अनुसार हम बेहतर मुसकान का अभ्यास कराते है। स्माइल मेकओवर क्लासेस में हंसने के तरीके के साथ ही चेहरे के हाव-भाव के बारे में भी बताया जाता है। ताकि हंसते समय आपके चेहरे का प्रभाव दूसरे पर अच्छा हो।

काया क्लीनिक की डॉ.चारुलता कहती है, चेहरे के आकार को देखकर हम यह अनुमान लगाने की कोशिश करते है कि आप पर कैसे दांत व कैसी मुसकान अच्छी लगेगी। फिर असली दांतों का आकार बदला जाता है व जरूरत पड़ी तो नकली दांत लगा दिया जाता है। दांतों का पूरा सेटअप बदलने के साथ यह बताया जाता है कि आपके लिए किस तरह हंसना ठीक रहेगा। हालांकि यह मौके पर निर्भर करता है। यानी मनचाही मुसकान जिसमें सब कुछ आकर्षक हो, वैसा हो, जैसा आप चाहे, हासिल की जा सकती है।

एक प्यारी सी मुसकान कई अनकही बातें कह जाती है और कई दिल जीत लेती है। आप इन बातों का ख्याल रख सकें तो चमचमाते दांत आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाएंगे और हर कोई कहेगा-स्माइल प्लीज।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक - नीलम सिंह गिल द्वारा देहात संदेश, गुरूद्वारा सुंदर सिंह रोड, जम्मू से प्रकाशित एवं नार्थलाईनस पबलिशर्स, 18-B, Phase- II, Industrial Estate, Gangyal, Jammu से मुद्रित। संपादक- नीलम सिंह गिल। फोन नंबरः- (95)191- 2574109 2548103 RNI Regd. No.: JKBIL/2004/13144 *Email: dehatsandesh@gmail.com, dehatsandesh@yahoo.com, dehatsandesh@rediffmail.com*

उपराज्यपाल ने वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी का दौरा किया, पैरा खिलाड़ियों से किया संवाद

श्रीनगर, 22 जुलाई। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने आज वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी (वीएमएस) का दौरा किया। यह संस्था पिछले पांच दशकों से जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, आजीविका और सामुदायिक समावेशन के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है। अपने दौरे के दौरान उपराज्यपाल ने संस्था के पदाधिकारियों और पैरा खिलाड़ियों के साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दिव्यांगजनों के समग्र सशक्तिकरण, पुनर्वास और पैरा खेलों के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की। वीएमएस के पदाधिकारियों, इसके संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉ. मीर मोहम्मद मकबूल तथा उपाध्यक्ष प्रो. मसूदा यासीन ने उपराज्यपाल से अनुकूलित (एडाप्टिव) खेलों के लिए मजबूत और व्यवस्थित तंत्र विकसित करने की मांग की। बैठक में फिजियोथेरेपी के लिए रोबोटिक उपकरण, बेहतर स्वास्थ्य एवं कौशल विकास सुविधाएं, जिला स्तर से अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू-कश्मीर पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की स्थापना, वर्षभर प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के लिए सभी मौसम में उपयोगी इंडोर पैरा स्पोर्ट्स हॉल का निर्माण तथा खिलाड़ियों की आवश्यकताओं जैसे विशेष खेल व्हीलचेयर, आधुनिक खेल उपकरण, कोचिंग शिविर, एक्सपोजर कार्यक्रम और यात्रा सहायता जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार दिव्यांगजनों के उत्थान और उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, हाल के वर्षों में जम्मू-कश्मीर के पैरा खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश के विशेष रूप से सक्षम युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचा और हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उपराज्यपाल ने वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी की पूरी टीम तथा इससे जुड़ी संस्थाओं की निस्वार्थ सेवा और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अनगिनत लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। उन्होंने पुनर्वास इकाइयों, वार्डों और अन्य सुविधाओं का भी निरीक्षण किया तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा, जब भी समाज में कोई सार्थक परिवर्तन होता है, उसके पीछे डॉ. मीर मोहम्मद मकबूल जैसे समर्पित लोग और यहां सेवा कर रहे सभी कर्मियों का योगदान होता है। आज मैं स्वयं को वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी से जुड़ा हुआ महसूस करता हूं, ठीक वैसे ही जैसे इसके पदाधिकारी और स्वयंसेवक पूरे समर्पण के साथ इस महान कार्य में लगे हुए हैं।

इस अवसर पर वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी के संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉ. मीर मोहम्मद मकबूल, उपाध्यक्ष प्रो. मसूदा यासीन, सचिव डॉ. फारूक अहमद कालू, कार्यकारी बोर्ड सदस्य इंजीनियर माजिद अहमद बाला, संस्था के कर्मचारी, प्रशिक्षक, कोच तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

उपराज्यपाल के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीनगर डॉ. जी. वी. सुंदीप चक्रवर्ती, उपायुक्त श्रीनगर अक्षय लाबरू तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन संख्या 12426 में 25 जुलाई को एक अतिरिक्त थर्ड एसी कोच लगाया जाएगा

जम्मू, 23 जुलाई। यात्रियों की भीड़ और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, *उत्तर रेलवे, जम्मू मंडल* द्वारा ट्रेन संख्या 12426 (जम्मू-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस) में 25 जुलाई 2026 को एक अतिरिक्त थर्ड एसी का कोच अस्थायी रूप से लगाया जाएगा।

इस व्यवस्था से यात्रियों को आरक्षण में अधिक विकल्प मिलेंगे और यात्रा अधिक आरामदायक हो सकेगी। अतिरिक्त कोच लगाने से ट्रेन में सीटों की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे प्रतीक्षा सूची में कमी आएगी और यात्रियों को अंतिम समय में भी कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी।

रेल प्रशासन का यात्रियों अनुरोध है, कि अपनी यात्रा से पहले आरक्षण की स्थिति की जानकारी वेबसाइट, हअश्वर्स ऐप या 139 हेल्पलाइन* से अवश्य प्राप्त कर लें।

यात्रियों की सुविधा और सेवा को बेहतर बनाना जम्मू मंडल की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

कश्मीर के कृषि निदेशक ने विभाग की बाढ़ संबंधी तैयारियों की समीक्षा की

श्रीनगर, 22 जुलाई (हि.स.)। कश्मीर के कृषि निदेशक सरताज अहमद शाह ने आज कश्मीर डिवीजन के सभी मुख्य कृषि अधिकारियों (सीएओ) के साथ एक वर्चुअल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की जिसमें बाढ़ की मौजूदा स्थिति का आकलन किया गया और खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान निदेशक ने जलभराव, फसल क्षति और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए फील्ड कर्मचारियों की तैयारियों पर रिपोर्ट सहित स्थिति का विस्तृत जिलावार आकलन किया। उन्होंने सभी मुख्य कृषि अधिकारियों को जिला प्रशासन के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और संवेदनशील कृषि क्षेत्रों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सरताज अहमद शाह ने सभी मुख्य कृषि अधिकारियों को संपूर्ण फील्ड मशीनरी को हाई अलर्ट पर रखने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी अधिकारी और कर्मचारी समय पर प्रतिक्रिया के लिए फील्ड में उपलब्ध रहें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जहां भी कृषि भूमि या खड़ी फसलें प्रभावित हुई हैं वहां तत्काल आकलन किया जाना चाहिए और किसानों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए।

प्राकृतिक आपदा प्रभावित परिवारों की सूची प्रमाणित, 22 परिवार चिन्हित

बसोहली, 22 जुलाई (हि.स.)। वर्ष 2025 में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित पात्र परिवारों की सूची प्रमाणित करने के लिए एडीसी बसोहली पंकज भगोत्रा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीपीओ बसोहली ओमप्रकाश, तहसीलदार बसोहली सागर विश्वकर्मा, तहसीलदार महानपुर राधिका सोहन, बीडीओ बसोहली राजेश कुमार, बीडीओ महानपुर मोतीलाल तथा पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि अगस्त-सितंबर 2025 की आपदा से प्रभावित लोगों के आवेदनों की जांच के बाद एसडीआरएफ मानकों के अनुसार राहत प्रदान की गई। समिति ने महानपुर के 7 और बसोहली के 15 भूमिहीन पात्र परिवारों को प्रमाणित कर सूची अनुमोदन हेतु डीसी कठुआ को भेजने का निर्णय लिया। एडीसी ने बारिश के मौजूदा हालात की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए।

नशा मुक्त जम्मू अभियान में 627 NDPS मामले, 713 आरोपी गिरफ्तार

जम्मू,, 22 जुलाई (हि.स.)। जम्मू पुलिस ने नशा मुक्त जम्मू अभियान के तहत नशा तस्करी और मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ चलाए गए अभियान की सफलता रिपोर्ट जारी की है। अभियान के दौरान जिले में 627 एनडीपीएस मामले दर्ज किए गए और 713 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 8.299 किलोग्राम हेरोइन, 40.042 किलोग्राम गांजा, 1 किलोग्राम अफीम और 3.25 किलोग्राम पोस्ता बरामद किया। नशा तस्करों की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए 28 बैंक खाते, लगभग 41 लाख रुपये और 123.290 ग्राम सोना फ्रीज किया गया।

कठुआ में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार का पुतला दहन, पुलिस से झड़प के बाद कार्यकर्ता हिरासत में

कठुआ, 22 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली के जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए लाठीचार्ज के विरोध में इंडियन यूथ कांग्रेस ने कठुआ में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका जिस पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनातनी की स्थिति बन गई।

प्रदर्शन के दौरान जैसे ही युवा कांग्रेस कार्यकर्ता पुतला दहन कर रहे थे कठुआ पुलिस मौके पर पहुंची और पुतला छीनने का प्रयास किया। इस दौरान स्थिति कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने बाद में कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया जिसके विरोध मे कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की।

यह प्रदर्शन युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष साहिल अंडोत्रा के नेतृत्व में आयोजित किया गया जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जता रहे थे लेकिन पुलिस ने जबरन हस्तक्षेप करते हुए पुतला छीन लिया और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जिसकी उन्होंने कड़ी निंदा की।

कार्यकर्ताओं ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है जिसे दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज को बर्बरता बताते हुए कहा कि उसी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कठुआ में यह प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उनका आरोप था कि छात्रों की आवाज दबाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि दिल्ली में लाठीचार्ज के दौरान कई पुलिसकर्मी बिना नेम प्लेट और कुछ लोग सिविल कपड़ों में मौजूद थे जिन्होंने भी बल प्रयोग किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि छात्रों की मांगों को अनदेखा किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंचा

जम्मू,, 22 जुलाई (हि.स.)। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़कर 35.0 फीट यानी खतरे के निशान पर पहुंच गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने तथा नदी के आसपास जाने से बचने की अपील की है। संबंधित विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।

अपनी पार्टी ने 25 करोड़ आपातकालीन बाढ़ फंड जारी करने की मांग की

जम्मू,, 22 जुलाई (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के प्रवक्ता रकीक अहमद खान ने प्रेस वार्ता के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राजौरी और पुंछ में आई विनाशकारी बाढ़ के बावजूद सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के लिए 25 करोड़ का आपातकालीन फंड जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों में देरी से लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं और क्षतिग्रस्त बाढ़ सुरक्षा कार्यों, सड़कों, पुलों तथा अन्य बुनियादी ढांचे की मरम्मत तत्काल शुरू की जानी चाहिए। रकीक अहमद खान ने राजौरी और पुंछ में पिछले चार दिनों से जारी बिजली संकट पर भी चिंता जताते हुए कहा कि अस्पताल भी पर्याप्त बिजली के बिना काम कर रहे हैं जिससे मरीजों की देखभाल प्रभावित हो रही है। उन्होंने बाढ़ में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 10 लाख मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी, घायलों को 5 लाख सहायता, क्षतिग्रस्त मकानों, दुकानों, पशुधन और फसलों का मुआवजा तथा बिजली सहित सभी आवश्यक सेवाओं की तत्काल बहाली की मांग की।
प्रेस वार्ता में पार्टी के अन्य नेताओं ने भी बाढ़ प्रभावित परिवारों के प्रति एकजुटता जताई।

उत्तर रेलवे

ई-निविदा सूचना

वरि. मण्डल विद्युत अभियंता/स./ उत्तर रेलवे/ जम्मू तवी द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से ई-निविदाएँ (**www.ireps.gov.in**) आमंत्रित की जाती हैं। निविदा कारक अपने मूल/संशोधित निविदा बंद होने की तिथि तथा समय तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

टेंडर संख्या	कार्यों का विवरण	अनुमानित लागत (₹)	बयाना राशि (₹.)	कार्य की अवधि	टेंडर खुलने की तिथि और समय	वेबसाईट
251-J-विद्युत-T-14-2026-27	जम्मू डिवीजन में गुड्स शेड पर 277 CCTV कैमरे लगाने से संबंधित विद्युत कार्य।	Rs. 17,13,576.10	34,300.00	06 माह	14.08.2026 15:00 बजे के बाद	www.ireps.gov.in

सं. 251-J-विद्युत/विद्युत- टेंडर नोटिस सं/14/2026-27, दिनांक : 22.07.2026 **2522/26**

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

उपायुक्त ने पटनीटॉप में क्लीन हिमालयन हिल सिटी पहल के क्रियान्वयन की समीक्षा की

उधमपुर, 22 जुलाई। उपायुक्त उधमपुर मिंगा शेरपा ने आज अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता कर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम के तहत क्लीन हिमालयन हिल सिटी पहल के क्रियान्वयन की रूपरेखा पर चर्चा की। इस पहल का उद्देश्य पटनीटॉप हिल स्टेशन का सतत विकास सुनिश्चित करना है।

उपायुक्त ने कहा कि यह पहल हिमालयी पर्वतीय नगरों में स्वच्छता, वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया एक विशेष कार्यक्रम है।

कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने पटनीटॉप विकास प्राधिकरण (पीडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को स्मार्ट सार्वजनिक शौचालयों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने, आवश्यक उपकरण एवं आधारभूत ढांचे की खरीद प्रक्रिया शुरू करने, सार्वजनिक कूड़ेदानों की स्थापना के लिए स्थान तय करने तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र को शीघ्र संचालित करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने संबंधित विभागों को अपशिष्ट कम करने, स्रोत स्तर पर कचरे के पृथक्करण तथा जिम्मेदार कचरा निस्तारण को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों के साथ परामर्श बैठकें और जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पटनीटॉप के स्वच्छ और प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित रखते हुए इसे एक सतत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के समन्वित प्रयासों पर बल दिया।

UNION TERRITORY OF JAMMU & KASHMIR

OFFICE THE EXECUTIVE ENGINEER PWD (R&B) DIVISION BASOHLI

Email:-xendivisionbasohli@yahoo.com

FRESH SHORT NOTICE INVITING TENDER (2ND CALL)

e-NIT No.48 of 2026-27 Dated 21-07-2026

For and on behalf of theLieutenant Governor, Union Territory of Jammu and Kashmire-tenders are invited on percentage basis from approved and eligible Contractors registered with Union Territory of J&K, CPWD, Railways, MES and other State/Central Governments for each of the following works :-

S. No	Name of Work	Name of Division	Advertised Cost(Rs. in lacs)	Cost of Tender document (in Rs.)	Earnest Money in shape of CDR/FDR /BG	Time Allowed for complete-on	Time and date of opening of tender	Class of Contractor
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Macadamization main road Laderi to Laderi Mohalla W.No.05 Plahi including link road from Sports stadium Pathiara to old BasohliPlassi road (Under City &Town Capex Budget 2026-27)	PWD (R&B) Divn. Basohli	60.00	1500/-	2% of Adv. Cost	03 Months	30-07-2026 (1200hrs Noon)	'A' Class
2	Macadamization of Basohli-Bani road to Baba Raja MandlikRehan falling in Basohli Rural Panchayat including link road Rehan Mandla Chanchloo Mata ji Km5th to 7th (Under City & TownCapex Budget 2026-27).	PWD (R&B) Divn. Basohli	60.00	1500/-	2% of Adv. Cost	03 Months	30-07-2026 (1200hrs Noon)	'A' Class
3	Macadamization of KathodaMorh to Chamunda Mata Mandir Ther (Panchayat Jankhar) including link road from PMGSY road to Sports stadium and Block HQ office Dhar Mahanpur (Under City & Town Capex Budget 2026-27).	PWD (R&B) Divn. Basohli	40.00	600/-	2% of Adv. Cost	03 Months	30-07-2026 (1200hrs Noon)	'A'& 'B' Class
4	Macadamization of link road from Trignaal to Dhanni (Kharmeth) (Under City & Town Capex Budget 2026-27).	PWD (R&B) Divn. Basohli	60.00	1500/-	2% of Adv. Cost	03 Months	30-07-2026 (1200hrs Noon)	'A' Class
5	Macadamization of Marta Km.1st NagrotaFarnot road to Bajod (Mahanpur- Basohli road) via SC Mohalla Adan in Ghagrore / Prehta / Plakh Panchayat including Marta NagrotaPlakhFarnot road in Km 8th (Under City & Town Capex Budget 2026-27).	PWD (R&B) Divn. Basohli	40.00	600/-	2% of Adv. Cost	03 Months	30-07-2026 (1200hrs Noon)	'A'& 'B' Class

No.1032-1049
Dated:-21-07-2026

DIP/J-6374/26
Dtd: 22-7-2026

Sd/-
Executive Engineer
PWD (R&B)
Division
Basohli

Note:- The tender documents can be seen and download from the website www.jktenders.gov.in

राजौरी में बाढ़ से भारी नुकसान, मंत्रियों ने लिया जायजा, प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बहाली कार्य तेज करने के निर्देश

राजौरी, 22 जुलाई (हि.स.)। हालिया फ्लैश फ्लड से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए जल शक्ति, वन पर्यावरण एवं जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा तथा युवा सेवा एवं खेल परिवहन समेत विभिन्न विभागों के मंत्री सतीश शर्मा ने बुधवार को राजौरी जिले का दौरा किया। मंत्रियों ने बेला कॉलोनी दरहाल सहित प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों से बातचीत की और मकानों, सड़कों, पेयजल व बिजली आपूर्ति समेत सार्वजनिक ढांचे को हुए नुकसान का आकलन किया। लगातार बारिश के कारण दरहाल, खंडली, सुकतोह और जमोला नालों में उफान से निचले क्षेत्रों में पानी भर गया जबकि दरहाल नदी ने बेला कॉलोनी के पास बाढ़ सुरक्षा दीवार तोड़ दी जिससे नए बस स्टैंड में भारी नुकसान हुआ। जावेद राणा ने कहा कि बाढ़ से सड़कों, पेयजल व बिजली व्यवस्था को व्यापक क्षति पहुंची है और कई ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क टूट गया है। उन्होंने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर बहाली कार्य तेज करने, पेयजल व बिजली आपूर्ति शीघ्र बहाल करने और क्षति का समयबद्ध आकलन कर प्रभावित परिवारों को राहत व मुआवजा देने के निर्देश दिए। सतीश शर्मा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत और जरूरी सेवाओं की बहाली सुनिश्चित करना है। मंत्रियों ने लोगों से मौसम संबंधी एडवाइजरी का पालन करने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाने से बचने की अपील भी की

संपादकीय

सुरक्षित परिस्थितियों का इंतजार करें

जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा भारी वर्षा, फ्लैश फ्लड और विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन की आशंका को देखते हुए श्री अमरनाथ जी यात्रा, माता वैष्णो देवी यात्रा, शिव खोरी यात्रा और माछैल माता यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय पूरी तरह उचित और दूरदर्शी है। यह भी सराहनीय है कि संबंधित अधिकारियों ने फंसे हुए श्रद्धालुओं के लिए ठहरने और भोजन की समुचित व्यवस्था करने के साथ-साथ पौष्टिक भोजन, चिकित्सा सुविधा और स्वच्छता जैसी आवश्यक सेवाएं भी सुनिश्चित की हैं।

यह उल्लेखनीय है कि मौसम विज्ञान विभाग (एमईटी) ने 19 जुलाई से 23 जुलाई 2026 के बीच जम्मू-कश्मीर में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी पहले ही जारी कर दी थी। हर वर्ष देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों श्रद्धालु जम्मू-कश्मीर के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित पवित्र तीर्थस्थलों की यात्रा करते हैं। इन यात्राओं की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार प्रशासन द्वारा की जाने वाली सूक्ष्म योजना होती है, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा आध्यात्मिक रूप से संतोषजनक, सुविधाजनक और सबसे बढ़कर सुरक्षित रहे।

हिमालय की भौगोलिक संरचना इन यात्राओं को अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। भारी वर्षा, भूस्खलन, बादल फटना और मौसम में अचानक बदलाव जैसी घटनाएं यहां कभी भी सामने आ सकती हैं। हाल के वर्षों में मौसम से जुड़ी कई दुखद घटनाएं सामने आई हैं। विशेष रूप से पिछले वर्ष माछैल माता यात्रा के दौरान बादल फटने की घटना में कई श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। ऐसे अनुभव यह स्पष्ट करते हैं कि प्रतिकूल मौसम के दौरान यात्राओं को रोकना श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

जब तक मौसम विभाग द्वारा जारी प्रतिकूल मौसम संबंधी चेतावनी प्रभावी है, तब तक प्रशासन और श्रद्धालुओं—दोनों को पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। सभी लोगों को संबंधित यात्रा बोर्डों और समितियों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन की रक्षा सबसे पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता है।

वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता धैर्य रखने और मौसम के पूरी तरह अनुकूल होने का इंतजार करने की है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लगातार और भारी बारिश समाप्त होने के बाद भी भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में जाना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि कई बार वर्षा रुकने के बाद भी पहाड़ खिसकने की घटनाएं होती हैं। इसलिए श्रद्धालुओं को अपनी यात्रा तभी दोबारा शुरू करनी चाहिए जब संबंधित अधिकारी औपचारिक रूप से इसकी अनुमति दें।

इन यात्राओं से जुड़े सभी लोगों को यह समझना चाहिए कि तीर्थयात्रा में कुछ दिनों की देरी एक छोटा-सा त्याग है, जबकि अनमोल मानव जीवन की क्षति की भरपाई कभी नहीं की जा सकती।

अंततः प्रशासन को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि श्रद्धालुओं को प्रतिकूल परिस्थितियों में यात्रा से रोकना उनकी आस्था पर रोक लगाना नहीं है, बल्कि सुशासन की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना ही प्रशासन का सबसे बड़ा दायित्व है और यही एक संवेदनशील तथा उत्तरदायी शासन की पहचान भी है।

एक महत्वपूर्ण बदलाव लाती है ई-जागृति

ई- जागृति उपभोक्ता शिकायत की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर इन संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करती है। ओटीपी आधारित पंजीकरण और ऑनलाइन दाखिल करने से लेकर डिजिटल जाँच, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, वर्चुअल सुनवाई, बहुभाषी आदेश और वास्तविक समय में मामले की निगरानी तक, यह प्लेटफ़ॉर्म नागरिकों को किसी भौगोलिक या प्रक्रियात्मक जटिलता की बाधा के बिना न्याय पाने में मदद करता है।

श्री प्रल्हाद जोशी

न्याय में देरी, लंबे समय से भारतीय उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ी निराशाओं में से एक रही है। चाहे वह खराब उत्पाद हो, ऑनलाइन खरीदी गई वस्तु का न मिल पाना हो, या अनुचित सेवा अनुबंध हो, शिकायत दर्ज करने से लेकर राहत पाने तक की प्रक्रिया अक्सर धीमी, बोझिल और डराने वाली रही है। हालांकि, भारत की उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था समय के साथ लगातार विकसित हुई है, लेकिन इसे समर्थन देने वाली प्रणाली तेज़ी से डिजिटल होती अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं के साथ कदम मिलाते हुए आगे नहीं बढ़ पायी।

आज, उपभोक्ता ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म, डिजिटल भुगतान प्रणाली और ऑनलाइन बाज़ार में बड़े पैमाने पर लेन-देन करते हैं। उपभोक्ता न्याय की पारंपरिक व्यवस्था—जो भौतिक रूप से दाखिल करने, व्यक्ति द्वारा एक-एक कर जांच करने, अलग-अलग सॉफ़्टवेयर प्लेटफार्म का उपुओग करने और आमने-सामने की सुनवाई के इर्द-गिर्द बनायी गयी थी—धीरे-धीरे अपर्याप्त सिद्ध होने लगी। डिजिटल युग में उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित करने के लिए केवल कानूनी सुधार ही पर्याप्त नहीं थे; इसके लिए न्याय देने के तरीके में पूरी तरह से बदलाव करने की जरूरत थी।

यहीं पर ई-जागृति एक महत्वपूर्ण बदलाव लाती है। यह सिर्फ़ एक तकनीक प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था के केंद्र में पहुंच, पारदर्शिता और दक्षता को रखकर उपभोक्ता विवाद समाधान के तरीके की नए सिरे से परिकल्पना करने का प्रयास है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में एक आधुनिक फ्रेमवर्क की परिकल्पना की गयी थी, जो बाज़ार की उभरती वास्तविकताओं के अनुरूप काम करने में सक्षम हो। हालाँकि, कानून की भावना को प्रभावी सार्वजनिक सेवा में बदलने के लिए कई अलग-अलग पुरानी प्रणालियों को हटाकर एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टम को अपनाने की जरूरत थी। पुराने प्लेटफॉर्म में एकरूपता की कमी, पुरानी संरचना, एक-दूसरे से जुड़कर काम करने की सीमित सुविधा और भौतिक प्रक्रियाओं पर अधिक निर्भरता जैसी समस्याएँ थीं। कई उपभोक्ताओं के लिए—विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन और अनिवासी भारतीय —न्याय पाने की प्रक्रिया की लागत अक्सर एक बड़ी बाधा बन जाती थी।

ई- जागृति उपभोक्ता शिकायत की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर इन संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करती है। ओटीपी आधारित पंजीकरण और ऑनलाइन दाखिल करने से लेकर डिजिटल जाँच, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, वर्चुअल सुनवाई, बहुभाषी आदेश और वास्तविक समय में मामले की निगरानी तक, यह प्लेटफ़ॉर्म नागरिकों को किसी भौगोलिक या प्रक्रियात्मक जटिलता की बाधा के बिना न्याय पाने में मदद करता है।

ऐसे बदलाव का महत्व केवल सुविधा तक ही सीमित नहीं है। यह नागरिकों और सार्वजनिक संस्थानों के बीच रिश्ते को मौलिक रूप से बदल देता है। डिजिटल वर्कफ़्लो कागजी काम को कम करते हैं, अलग-अलग अधिकार-क्षेत्रों में प्रक्रियाओं को एक जैसा बनाते हैं, विवेकाधीन देरी को कम करते हैं और पारदर्शिता बढ़ाते हैं। मामलों की स्वचालित सूची, ऑनलाइन डैशबोर्ड और तुरंत सूचना सुनिश्चित करती है कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान शिकायतकर्ता को हर जानकारी मिलती रहे, जिससे प्रणाली में जनता का भरोसा मजबूत होता है।

इस प्लेटफ़ॉर्म ने न्याय को और अधिक समावेशी बनाने के लिए उभरती तकनीकों को भी अपनाया है। एआई-सहायता प्राप्त मामला विश्लेषण, वॉइस-टू-टेक्स्ट कार्यप्रणाली, टेक्स्ट-टू-स्पीच सुविधा, बहुभाषी इंटरफेस, उन्नत सर्च क्षमता और पहुँच प्राप्त करने के उपकरण जैसी विशेषताओं के जरिए समाज के विभिन्न हिस्सों से अधिक लोगों की भागीदारी संभव हुई है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और राज्य उपभोक्ता आयोगों में हाइब्रिड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का देश भर में लागू होना भी उतना ही अहम रहा है, जिससे वर्चुअल सुनवाई उपभोक्ता न्याय दिलाने की प्रक्रिया का एक ज़रूरी हिस्सा बन गई है। दूरदराज के जिलों या विदेशों में रहने वाले नागरिकों के लिए, इससे कानूनी लड़ाई की वित्तीय और लॉजिस्टिक लागत दोनों काफी हद तक कम हो गई हैं।

फिर भी, इस स्तर के तकनीकी बदलाव में चुनौतियाँ हमेशा मौजूद रहती हैं। डिजिटल सुधार अक्सर संस्थानों को स्थापित प्रथाओं पर फिर से सोचने के लिए मजबूर करते हैं और उपयोगकर्ताओं को अपरिचित प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ई-जागृति की शुरुआत के दौरान, डेटा स्थानान्तरण, भुगतान गेटवे एकीकरण, इंटरफेस की उपयोगिता और लंबे समय से चल रहे मैनुअल प्रक्रियाओं में बदलाव को लेकर चिंताएँ उभरीं। कानूनी पेशेवरों और अन्य हितधारकों के कुछ हिस्सों ने नई डिजिटल व्यवस्था को अपनाते समय कुछ चिंताएं जाहिर कीं।

इन चिंताओं को बाधा मानने की बजाय, कार्यान्वयन प्रक्रिया ने उन्हें निरंतर सुधार के मौकों के तौर पर देखा। उपभोक्ता आयोगों, कानूनी पेशेवरों, तकनीकी विशेषज्ञों और राय सरकारों के साथ व्यापक परामर्श से इस प्लेटफ़ॉर्म को बेहतर बनाने में मदद मिली। नियमित क्षमता निर्माण कार्यक्रम, क्षेत्रीय कार्यशालाएं, वर्चुअल प्रशिक्षण सत्र, साप्ताहिक शिकायत निवारण संवाद और लगातार तकनीकी समर्थन से हितधारकों का नई प्रणाली में धीरे-धीरे भरोसा बढ़ा। इस अनुभव से एक महत्वपूर्ण सबक मिला- डिजिटल परिवर्तन केवल इसलिए सफल नहीं होता कि तकनीक लागू की गई है, बल्कि इसलिए सफल होता है, क्योंकि संस्थाएं उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया के प्रति संवेदनशील रहती हैं और निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध रहती हैं।

शुरुआती परिणाम उत्साहवर्धक हैं। थोड़े ही समय में, ई-जागृति ने लाखों उपभोक्ताओं को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला दिया है, दो लाख से अधिक मामलों के दाखिले की सुविधा दी है, उच्च समाधान दर हासिल की है और साठ से अधिक देशों के उपभोक्ताओं को भारत के उपभोक्ता विवाद निवारण व्यवस्था तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। मानकीकृत डिजिटल वर्कफ़्लो ने दक्षता में सुधार किया है और उन प्रक्रियात्मक अड़चनों को कम किया है, जो पहले की प्रणाली की विशेषता थी।

राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार के माध्यम से मान्यता, न केवल एक संस्थागत उपलब्धि के रूप में, बल्कि सरकारी प्रक्रिया की सफल पुनः डिज़ाइन की स्वीकृति के रूप में महत्वपूर्ण है। यह पुरस्कार इस बात को मान्यता देता है कि सार्थक डिजिटल शासन केवल मौजूदा प्रक्रियाओं को कंप्यूटरीकृत करने के बारे में नहीं है; यह उन्हें सरल, तेज़ और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए फिर से डिज़ाइन करने के बारे में है।

भारत की व्यापक डिजिटल इंडिया यात्रा ने दिखाया है कि जब मजबूत संस्थागत प्रतिबद्धता हो, तो तकनीक सार्वजनिक सेवा अदायगी को बदल सकती है। डिजिटल पहचान और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से लेकर ऑनलाइन कराधान और स्वास्थ्य देखभाल प्लेटफार्मों तक, देश ने शासन में तकनीक की भूमिका का लगातार विस्तार किया है। अब उपभोक्ता न्याय भी उन क्षेत्रों की सूची में शामिल हो गया है, जिसमें संरचनात्मक डिजिटल सुधार हो रहे हैं।

ई-जागृति की सफलता भविष्य के शासन सुधारों के लिए भी महत्वपूर्ण सबक देती है। डिजिटल प्लेटफार्मों को संस्थाओं के बजाय नागरिकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाना चाहिए। पहुंच को बाद में सोची जाने वाली बात के बजाय एक मूल सिद्धांत के रूप में लिया जाना चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को निष्पक्षता से समझौता किए बिना पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सबसे बढ़कर, तकनीक को न्याय को सरल बनाना चाहिए, न कि उसमें जटिलता की नई परतें जोड़नी चाहिए।

जैसे-जैसे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है, उपभोक्ता का विश्वास उन संस्थाओं की विश्वसनीयता पर अधिक निर्भर करेगा, जो उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करती हैं। प्रभावी विवाद समाधान अब केवल एक प्रशासनिक उद्देश्य नहीं रहा; यह एक आर्थिक आवश्यकता बन गया है, जो बाजारों में भरोसे को मजबूत करता है और जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देता है। ई-जागृति प्लेटफार्म दिखाता है कि सोच-समझकर किया गया डिजिटल बदलाव कानूनी इरादे और नागरिक अनुभव के अंतर को कम कर सकता है। उपभोक्ता न्याय को तेज़, अधिक पारदर्शी और अधिक समावेशी बनाकर, यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत को मजबूत करता है—कि डिजिटल लोकतंत्र में, न्याय तक पहुंच भी सेवा तक पहुंच जितनी ही सहज होनी चाहिए। यही शायद इक्कीसवीं सदी में ग्राहक देवो भव का सबसे सार्थक रूप है।

(लेखक केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं)

जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के क्षरण, प्रदूषण जैसी अभूतपूर्व चुनौतियों से जूझ रही है दुनिया

- योगेश कुमार गोयल

भारतीय संस्कृति में प्रकृति को सदैव पूजनीय माना गया है। हमारे पर्व और उत्सव केवल सामाजिक उल्लास के अवसर नहीं रहे बल्कि प्रकृति और मानव के सह अस्तित्व के प्रतीक भी रहे हैं। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के क्षरण, प्रदूषण और जल संकट जैसी अभूतपूर्व चुनौतियों से जूझ रही है, तब भारत में 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाने वाला 'वन महोत्सव' केवल वृक्षारोपण का अभियान नहीं बल्कि पृथ्वी पर जीवन बचाने का राष्ट्रीय संकल्प बन चुका है। वास्तव में वर्तमान समय की आवश्यकताओं को देखा जाए तो वन महोत्सव से बड़ा कोई उत्सव नहीं हो सकता क्योंकि इसका संबंध केवल पर्यावरण से नहीं बल्कि मानव सभ्यता के भविष्य से है।

भारतीय परंपरा में वनों को देवतुल्य माना गया है। वे केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि पृथ्वी के फेफड़े, जैव विविधता के सबसे बड़े आश्रय, नदियों के संरक्षक, जलवायु संतुलन के प्रहरी तथा करोड़ों लोगों की आजीविका के आधार हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से ठीक पहले जुलाई 1947 में दिल्ली में चलाए गए व्यापक वृक्षारोपण अभियान ने वन महोत्सव की अवधारणा को जन्म दिया था, जिसे वर्ष 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। जुलाई के प्रथम सप्ताह का चयन इसलिए किया गया क्योंकि दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान मिट्टी में पर्याप्त नमी होने से पौधों के जीवित रहने की संभावना सर्वाधिक रहती है। आज यह अभियान भारत के 'वसुधैव कुटुम्बकम' के दर्शन का जीवंत प्रतीक बन चुका है।

वनों की स्थिति विश्व स्तर पर चिंताजनक बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, पृथ्वी का केवल लगभग 31 प्रतिशत भूभाग ही वनाच्छादित है जबकि प्रतिवर्ष लाखों हेक्टेयर वन क्षेत्र अवैध कटाई, औद्योगिकीकरण, खनन और अवसंरचनात्मक विकास की भेंट चढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो आगामी दशकों में विश्व के अनेक वर्षावन गंभीर संकट में पड़ सकते हैं। ऐसे समय में भारत जैसे विशाल और जैव विविधता से समृद्ध देश की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। भारत ने हाल के वर्षों में वन संरक्षण और वृक्षारोपण की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए हैं।भारतीय वन सर्वेक्षण की भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) के अनुसार, देश का कुल वन एवं वृक्ष आवरण बढ़कर 8,27,357 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17 प्रतिशत है। इसमें 7,15,343 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र तथा 1,12,014 वर्ग किलोमीटर वृक्ष आवरण शामिल है। पिछले आकलन की तुलना में कुल हरित आवरण में 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है जबकि अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ उसके बाद आते हैं। वहीं, वन घनत्व के अनुपात में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय अग्रणी हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट में भारत को कुल वन क्षेत्र के आधार पर विश्व में नौवां स्थान तथा वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में अग्रणी देशों में स्थान प्राप्त हुआ है।

हालांकि इन उपलब्धियों के साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि हरित आवरण में हुई वृद्धि का बड़ा हिस्सा प्राकृतिक सघन वनों के बजाय खुले वनों तथा व्यावसायिक वृक्षारोपण के कारण हुआ है। प्राकृतिक वन केवल पेड़ों का समूह नहीं होते बल्कि हजारों वनस्पतियों, जीव-जंतुओं, सूक्ष्म जीवों और जल स्रोतों का जटिल पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। इनका स्थान कृत्रिम पौधारोपण कभी नहीं ले सकता। विशेष चिंता का विषय पूर्वोत्तर भारत है, जहां सड़क निर्माण, जलविद्युत परियोजनाओं, झूम खेती, भूस्खलन तथा अन्य विकास गतिविधियों के कारण कई क्षेत्रों में वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है। दूसरी ओर विकास परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई के बाद प्रतिपूरक वृक्षारोपण तो किया जाता है लेकिन पौधों की देखभाल, सिंचाई और संरक्षण की अनदेखी के कारण उनमें से अधिकांश जीवित नहीं रह पाते। केवल पौधे लगा देना पर्याप्त नहीं है बल्कि उन्हें वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखना ही वास्तविक सफलता है।

आज वन मानव स्वास्थ्य के सबसे बड़े संरक्षक बन चुके हैं। वायु प्रदूषण, जल संकट और भूमि के मरुस्थलीकरण जैसी समस्याओं का सबसे प्रभावी और किफायती समाधान वृक्ष ही हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर जलवायु परिवर्तन की गति को धीमा करते हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं, वर्षा चक्र को संतुलित रखते हैं, भूजल स्तर बनाए रखते हैं तथा मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। बढ़ते प्रदूषण के कारण कैंसर, हृदय रोग, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों से संबंधित बीमारियों में तेजी से वृद्धि हो रही है। साथ ही, अनियमित मानसून, भीषण हीटवेव, सूखा, क्लाउडबर्स्ट और जंगलों में आग जैसी घटनाएं स्पष्ट संकेत हैं कि प्रकृति का संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है। इस संकट से निपटने के लिए भारत ने वर्ष 2030 तक अतिरिक्त 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन सिंक विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें वनों की भूमिका निर्णायक होगी।

बहरहाल, वन महोत्सव का वास्तविक संदेश केवल सप्ताह भर लाखों पौधे लगाने तक सीमित नहीं है बल्कि इसकी सफलता इस बात में निहित है कि स्थानीय जलवायु के अनुरूप नीम, पीपल, बरगद, बेल, जामुन, अर्जुन और अन्य देशज प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाए तथा प्रत्येक पौधे की कम-से-कम तीन वर्षों तक नियमित देखभाल सुनिश्चित की जाए। जब तक पौधारोपण को जनभागीदारी और जन जिम्मेदारी का अभियान नहीं बनाया जाएगा, तब तक हरित भारत का सपना अधूरा रहेगा।

विकास और पर्यावरण परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं। आर्थिक प्रगति, आधुनिक तकनीक और अवसंरचनात्मक विकास आवश्यक हैं किंतु वे स्वच्छ वायु, शुद्ध जल और संतुलित जलवायु का विकल्प नहीं बन सकते। यदि वन सुरक्षित रहेंगे तो नदियां जीवित रहेंगी, भूजल समृद्ध होगा, जैव विविधता संरक्षित रहेगी और मानव सभ्यता का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए वन महोत्सव केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व और राष्ट्रीय आंदोलन बनना चाहिए। आज आवश्यकता केवल वृक्ष लगाने की नहीं बल्कि उन्हें बचाने की भी है क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हमसे विकास की ऊंची इमारतें नहीं बल्कि सांस लेने योग्य स्वच्छ पृथ्वी की विरासत चाहेंगी।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

सिंथेटिक ओपिओइड- अमेरिका में कानून और स्वास्थ्य के बीच संतुलन

सैयद सुलेमान अख्तर, स्पैन पत्रिका

अवैध सिंथेटिक दवाओं का बढ़ता प्रचलन वैश्विक मादक पदार्थों के परिदृश्य को बदल रहा है। पारंपरिक मादक पदार्थों के विपरीत, फेंटानिल जैसे सिंथेटिक ओपिओइड को तेजी से बनाया जा सकता है, जटिल अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है और भौतिक तथा ऑनलाइन दोनों नेटवर्कों के जरिए वितरित किया जा सकता है। इनकी बढ़ती व्यापकता ने सरकारों को यह सोचने के लिए मजबूर किया है कि वे मादक पदार्थों की तस्करी और लत से कैसे निपटें।

जब पत्रकार प्रांजित डेका और नीति विशेषज्ञ अयाज अहमद वानी इस वर्ष की शुरुआत में मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर केंद्रित आईवीएलपी कार्यक्रम के तहत अमेरिका गए, तो उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया देखी जो पारंपरिक कानून प्रवर्तन से कहीं आगे तक जाती है। नीति निर्माताओं, कानून प्रवर्तन अधिकारियों, शोधकर्ताओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ बैठकों के दौरान उन्होंने देखा कि अमेरिका बदलते मादक पदार्थों के खतरों से निपटने के लिए खुफिया जानकारी, प्रवर्तन, उपचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को किस प्रकार जोड़ता है।

वानी के अनुसार, सिंथेटिक ओपिओइड अमेरिका में एक बड़ी राष्ट्रीय चिंता बन चुके हैं। हाल के वर्षों में देश में ओवरडोज से होने वाली मौतों में वृद्धि देखी गई है, जिसका मुख्य कारण सिंथेटिक ओपिओइड, मेथामफेटामाइन और कोकीन का उपयोग रहा है। चुनौती के व्यापक स्तर को देखते हुए अमेरिका की प्रतिक्रिया में मादक पदार्थों की तस्करी और लत को तेजी से ऐसे मुद्दों के रूप में देखा जा रहा है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को प्रभावित करते हैं। वानी ने बताया कि फेंटानिल, जिसके कारण हर साल हजारों मौतें होती हैं, को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़े खतरे के रूप में देखा जाता है।

इसके परिणामस्वरूप, अमेरिकी एजेंसियां, वानी के अनुसार 卐संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण卐 अपनाती हैं, जिसमें सीमा सुरक्षा, प्रतिबंध, खुफिया जानकारी एकत्र करना, संपत्ति जब्त करना, कूटनीतिक भागीदारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय शामिल हैं। इस रणनीति का उद्देश्य केवल तस्करी नेटवर्क को बाधित करना ही नहीं बल्कि उपचार, रोकथाम और सामुदायिक पहुंच के माध्यम से मांग को कम करना भी है।

यात्रा के दौरान उभरकर सामने आए सबसे मजबूत पहलुओं में से एक खुफिया-आधारित पुलिसिंग का महत्व था। सिंथेटिक ओपिओइड को केवल स्थानीय कानून प्रवर्तन की समस्या मानने के बजाय, अमेरिकी एजेंसियां उन आपराधिक नेटवर्कों पर ध्यान केंद्रित करती हैं जो इनका उत्पादन, परिवहन, वित्तपोषण और वितरण करते हैं। डेका कहते हैं, 卐यहां अमेरिकी दृष्टिकोण अत्यधिक खुफिया-आधारित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केंद्रित है। सिंथेटिक ओपिओइड को स्थानीय मुद्दा नहीं माना जाता, बल्कि इसे वैश्विक आपराधिक नेटवर्क के हिस्से के रूप में देखा जाता है। ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए) के साथ बैठकों के दौरान, आईवीएलपी प्रतिभागियों ने सीखा कि विभिन्न देशों में तस्करी मार्गों का पता कैसे लगाया जाता है और एजेंसियां मादक पदार्थों के वितरण के लिए इस्तेमाल होने वाले वित्तीय प्रवाह तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की निगरानी कैसे करती हैं।

टेक्सास में होमलैंड सिक्योरिटी विभाग और नेशनल नेटवर्क ऑफ फ्यूजन सेंटर्स के साथ बैठकों ने यह दिखाया कि सीमा अधिकारियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और वित्तीय जांचकर्ताओं द्वारा एकत्र की गई जानकारी को किस प्रकार एक साथ लाकर वास्तविक समय में विश्लेषित किया जाता है। डेका कहते हैं, 卐इस प्रकार की वास्तविक समय में कई स्रोतों से खुफिया जानकारी साझा करना सिंथेटिक दवाओं से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हें पारंपरिक मादक पदार्थों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बनाया और तस्करी किया जा सकता है। वानी भी अंतर एजेंसी सहयोग की भूमिका पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि डीईए, एफबीआई और होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस के फ्यूजन केंद्र मादक पदार्थ नेटवर्कों की निगरानी के लिए मिलकर काम करते हैं, जबकि फेडेरल, राज्य और स्थानीय कार्यबल जानकारी साझा करते हैं और जांच का समन्वय करते हैं।

जहां कानून प्रवर्तन अमेरिका की प्रतिक्रिया का एक केंद्रीय हिस्सा बना हुआ है, वहीं प्रतिभागियों ने रोकथाम, उपचार और पुनर्वास पर दिए गए जोर को भी महत्वपूर्ण पाया। डेका कहते हैं, 卐जिस बात ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया, वह सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण की ओर स्पष्ट बदलाव था। लत को केवल एक आपराधिक मुद्दा नहीं माना जाता बल्कि एक पुरानी स्वास्थ्य स्थिति के रूप में देखा जाता है, जिसके लिए उपचार और सहायता की आवश्यकता होती है। मिशिगन में उन्होंने एंजल पहल जैसे कार्यक्रमों को देखा, जो नशे की समस्या से जूझ रहे लोगों को बिना सजा के डर के सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शोधकर्ताओं के साथ चर्चाओं में रोकथाम शिक्षा, सामुदायिक भागीदारी और शुरुआती हस्तक्षेप की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। वानी के अनुसार, सामुदायिक भागीदारी व्यापक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह बताते हैं कि स्वास्थ्यकर्मी, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, स्थानीय अधिकारी और सामुदायिक संगठन मिलकर मांग को कम करने और उपचार तक पहुंच बढ़ाने के लिए काम करते हैं। वह कहते हैं, 卐अमेरिका नशीली दवाओं की लत और पदार्थों के उपयोग को एक पुरानी बीमारी के रूप में देखता है और समुदायों को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से नारकैन जैसे उपचार तक पहुंच प्रदान की जाती है।

डेका लंबे समय तक नशामुक्ति में सहायता के लिए दवा-सहायता प्राप्त उपचार और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग की ओर भी संकेत करते हैं।

कॉमनवेल्थ गेम्स में दमदार शुरुआत के लिए तैयार विशाल टीके, बोले- देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा

एजेंसी

मुंबई। भारतीय क्वार्टर-माइलर विशाल थेन्नारासु कयालविझी (विशाल टीके) ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स-2026 में अपने पहले अभियान के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 22 वर्षीय विशाल इस सीजन शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत के शीर्ष स्प्रिंट धावकों में अपनी पहचान बना चुके हैं। उन्होंने इसी वर्ष 400 मीटर दौड़ में 44.98 सेकेंड का समय निकालकर 45 सेकेंड का आंकड़ा तोड़ने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बनने का इतिहास रचा था। यह प्रदर्शन मौजूदा राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। चार बार के राष्ट्रीय चैंपियन विशाल ने हाल के वर्षों में एशियाई स्तर पर भी अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को मिक्स्ड 4×400 मीटर रिले में स्वर्ण और पुरुष 4×400 मीटर रिले में रजत पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। विश्व रैंकिंग में शीर्ष-60 धावकों में शामिल विशाल अब कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की सबसे बड़ी उम्मीदों में गिने जा रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में पदार्पण से पहले विशाल ने कहा, मैं जीत की मानसिकता के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में उतर रहा हूं। कई महीनों की कड़ी मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन, निरंतरता और आत्मविश्वास ने मुझे यहां तक पहुंचाया है।

तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार-2025 के लिए 20 अगस्त तक होंगे ऑनलाइन नामांकन

नई दिल्ली। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार (टीएनएनएए) 2025 के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। भारत में साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाले इस सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 जुलाई से 20 अगस्त तक खुली रहेगी। इच्छुक उम्मीदवार गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार का उद्देश्य साहसिक खेलों में असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करना तथा युवाओं में साहस, धैर्य, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना को बढ़ावा देना है। यह पुरस्कार चार श्रेणियों–स्थल (लैंड) साहसिक, जल (समुद्र) साहसिक, वायु साहसिक और आजीवन उपलब्धि–में प्रदान किया जाता है। साथ ही इसका उद्देश्य देश के युवाओं को साहसिक गतिविधियों में अधिक भागीदारी के लिए प्रेरित करना भी है। पुरस्कार विजेताओं को कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र, ब्लेज़र (या साड़ी) तथा 15 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। इस पुरस्कार का दर्जा अर्जुन पुरस्कार के समकक्ष है और इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के साथ प्रदान किया जाता है।

चेल्सी फुटबॉल क्लब से जुड़े इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी मॉर्गन रोजर्स, 7 साल का हुआ करार

लंदन । चेल्सी फुटबॉल क्लब ने इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी मॉर्गन रोजर्स को एस्टन विला से साइन कर लिया है। प्रीमियर लीग क्लब ने कहा कि 23 साल के खिलाड़ी ने 2033 तक स्टैमफोर्ड ब्रिज में रहने के लिए सात साल की डील साइन की है। चेल्सी ने मिडफील्डर को कथित तौर पर 117 मिलियन पाउंड की डील पर साइन किया है, जिससे वह अब तक के सबसे महंगे ब्रिटिश खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस गर्मी की शुरुआत में इलियट एंडरसन के 116 मिलियन पाउंड में मैनचेस्टर सिटी में शामिल होने का रिकॉर्ड तोड़ा है। क्लब द्वारा जारी एक बयान में रोजर्स ने कहा, 'मैं बहुत उत्साहित हूं। मेरे लिए चेल्सी लंदन का सबसे बड़ा क्लब है और एक ऐसा क्लब है जिसकी मैं बचपन से तारीफ करता रहा हूं। मैं नए मैनेजर के साथ प्रोजेक्ट, हमारे पास मौजूद खिलाड़ियों और क्लब की दिशा को लेकर बहुत उत्साहित हूं। इसी वजह से मैं यहां हूं, और क्लब की तरफ से खेलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ' आर्सेनल ने इस ट्रांसफर विंडो में मॉर्गन रोजर्स को अपनी पहली पसंद के फॉरवर्ड के रूप में देखा था। हालांकि, क्लब ने उतनी ट्रांसफर फीस देने से इनकार कर दिया, जितनी प्रीमियर लीग 2025-26 चैंपियन चेल्सी देने के लिए तैयार थी। इसलिए आर्सेनल इस डील को पूरा नहीं कर सका।

14वीं सेंट सोल्जर फुटबॉल ट्रॉफी का जोश और खेल भावना के साथ आगाज़

चंडीगढ़। सेंट सोल्जर इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर-28 बी, चंडीगढ़ में 14वीं सेंट सोल्जर फुटबॉल ट्रॉफी का शानदार आगाज़ हुआ। 21 जुलाई से 24 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाले इस प्रतिष्ठित चार दिवसीय टूर्नामेंट में ट्राईसिटी के विभिन्न प्रमुख स्कूलों के युवा फुटबॉल खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और खेल भावना का प्रदर्शन करने का बेहतरीन मंच प्रदान कर रही है। उद्घाटन समारोह में स्कूल के चेयरमैन रविंदरपाल सिंह हेयर, डायरेक्टर जगविंदरपाल सिंह हेयर, एडवाइजर विजया सिद्धू और प्रिंसिपल अनीशा घुमन विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने सभी प्रतिभागी टीमों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने खिलाड़ियों को अनुशासन, समर्पण और सच्ची खेल भावना के साथ मैदान में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। टूर्नामेंट के उद्घाटन मुकाबले में सेंट कबीर स्कूल, सेक्टर-26 और मोती राम आर्य स्कूल, सेक्टर-27 के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। सेंट कबीर स्कूल ने शानदार टीमवर्क और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए 4-2 से जीत दर्ज की। टीम के लिए अरिवाज ने 17वें मिनट में पहला गोल किया, जबकि नवराज ने 21वें मिनट में बढ़त को मजबूत किया। इसके बाद गुरकीरत ने 35वें मिनट में तीसरा और शबद ने 40वें मिनट में चौथा गोल दागा।

ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में इन भारतीय खिलाड़ियों पर रहेंगी पदक की सबसे बड़ी उम्मीदें

एजेंसी

नई दिल्ली। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय दल एक बार फिर दमदार प्रदर्शन के इरादे से उतरेगा। अनुभवी सितारों और युवा खिलाड़ियों के मिश्रण वाली भारतीय टीम से कई स्पर्धाओं में पदक की उम्मीद की जा रही है। खासकर नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहैन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों पर देश की नजरें टिकी होंगी। इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में 74 देशों और क्षेत्रों के तीन हजार से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, तैराकी, कलात्मक जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग, नेटबॉल, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी, जूडो, बाउल्स और 3×3 बास्केटबॉल समेत 10 खेल शामिल हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा एक बार फिर भारतीय चुनौती की अगुआई करेंगे। उनसे स्वर्ण पदक की सबसे मजबूत उम्मीद मानी जा रही है।

मीराबाई चानू रच सकती हैं गोल्ड की हैट्रिक

भारोत्तोलन में भारत की स्टार खिलाड़ी मीराबाई चानू अब तक राष्ट्रमंडल खेलों में दो स्वर्ण और एक रजत पदक जीत चुकी हैं। उन्होंने 2018 गोल्ड कोस्ट और 2022 बर्मिंघम खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। ग्लासगो में वह लगातार तीसरा स्वर्ण जीतकर इतिहास रचने के इरादे से उतरेंगी।

लवलीना बोरगोहैन से मुक्केबाजी में बड़ी आस

टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता और 2023 विश्व चैंपियन लवलीना बोरगोहैन महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में भारत की सबसे बड़ी पदक दावेदार होंगी। अपनी निरंतरता और अनुभव के दम पर उनसे स्वर्ण पदक की उम्मीद की जा रही है।

गुरिंदरवीर सिंह पर होगी सबकी नजर- भारत के सबसे तेज धावक गुरिंदरवीर सिंह ने इस वर्ष 100 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए 10.09 सेकंड का समय निकाला था। राष्ट्रमंडल खेलों में वह पहली बार हिस्सा लेंगे और एथलेटिक्स में भारत के लिए पदक जीतने की क्षमता रखते हैं। अनुभवी जिम्नास्ट प्रणति नायक कलात्मक जिम्नास्टिक में भारत की चुनौती का नेतृत्व करेंगी। उनका लक्ष्य राष्ट्रमंडल खेलों में पहला पदक जीतकर इतिहास रचना होगा। इन दिग्गज खिलाड़ियों के अलावा सरवेश कुशारे और ज्ञानेश्वरी यादव जैसे युवा खिलाड़ी भी पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेंगे। उनसे भविष्य की मजबूत भारतीय टीम की नींव रखने वाले प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है।

घुटने की चोट के कारण द हंड्रेड 2026 से बाहर हुए जैकब बेथेल, पाकिस्तान टेस्ट सीरीज पर भी संकट

एजेंसी

लंदन। इंग्लैंड के युवा ऑलराउंडर जैकब बेथेल घुटने की चोट के कारण द हंड्रेड 2026 से बाहर हो गए हैं। बेथेल इस बार बर्मिंघम फीनिक्स की कप्तानी करने वाले थे, लेकिन चोट के चलते अब वह टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसके साथ ही अगस्त में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में उनका खेलना भी संदेह के घेरे में आ गया है।

बर्मिंघम फीनिक्स की ओर से जारी बयान में कहा गया, 22 वर्षीय जैकब बेथेल इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) की मेडिकल टीम की निगरानी में अपना पुनर्वास कार्यक्रम जारी रखेंगे। आने वाले कुछ सप्ताह वह पूरी तरह फिट होने पर ध्यान देंगे।बेथेल आखिरी बार भारत के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में मैदान पर उतरे थे। उन्होंने तीन मैचों में 109 रन बनाए और 36.33 की औसत से बल्लेबाजी की। श्रृंखला के निर्णायक मुकाबले में 91 रन बनाने और 49 रन देकर एक विकेट लेने के शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था।

चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर होने पर बेथेल ने कहा, द हंड्रेड में नहीं खेल पाना बेहद निराशाजनक है।

विश्व कप जीत के बाद भावुक हुए पेड्री और दानी ओल्मो, बोले- यह सफलता पूरे स्पेन की

एजेंसी

मैड्रिड। फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जीतने के बाद स्पेन के स्टार फुटबॉलर पेड्री गोंजालेज और दानी ओल्मो ने प्रशंसकों के नाम भावुक संदेश साझा करते हुए उनके अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। दोनों खिलाड़ियों ने कहा कि यह ऐतिहासिक सफलता पूरे स्पेन की है।

स्पेन ने विश्व कप 2026 के फाइनल में गत चैंपियन अर्जेंटीना को अतिरिक्त समय में 1-0 से हराकर इतिहास रचते हुए अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीता। विश्व कप जीत के बाद राजधानी मैड्रिड सहित पूरे स्पेन में जश्न का माहौल रहा। हजारों प्रशंसकों के साथ जीत का उत्सव मनाने के बाद मिडफील्डर दानी ओल्मो ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, अब भी मेरे पास शब्द नहीं हैं। कल के जश्न में हमारे साथ शामिल होने और पूरे विश्व कप के दौरान लगातार हमारा साथ देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। वहीं, स्पेन के युवा मिडफील्डर पेड्री गोंजालेज ने भी भावुक संदेश साझा करते हुए लिखा, सबसे बड़ी सफलता मेरे अपने लोग

हैं। हमने साथ मिलकर सपने देखे और साथ मिलकर यह सफर तय किया। फाइनल मुकाबले में अतिरिक्त समय के 106वें मिनट में स्थानापन्न खिलाड़ी फेरान टोरेस ने निर्णायक गोल कर स्पेन को 1-0 की जीत दिलाई। निको विलियम्स के हेडर पर मिले पास को टोरेस ने गोल में बदलकर स्पेन को विश्व चैंपियन बना दिया।मुख्य कोच लुइस डे ला फुएंते की टीम ने पूरे मुकाबले में दबदबा बनाए रखा और लगातार गोल के मौके बनाए। हालांकि, अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने 12 शानदार बचाव कर अपनी टीम को लंबे समय तक मुकाबले में बनाए रखा, लेकिन अंततः टोरेस के गोल ने स्पेन को ऐतिहासिक जीत दिला दी। इस जीत के साथ स्पेन ने 16 वर्षों बाद फिर से फीफा विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम की। इससे पहले उसने 2010 में पहली बार विश्व कप जीता था। विश्व कप 2026 में स्पेन पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहा और यूईएफए यूरो 2024 खिताब के बाद एक और बड़ी अंतरराष्ट्रीय सफलता अपने नाम की।

विश्व कप फाइनल में हार के बाद मार्टिनेज भावुक, बोले- परिणाम हमारी पूरी यात्रा को परिभाषित नहीं करता

एजेंसी

ब्यूनस आयर्स। फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में स्पेन के खिलाफ हार के बाद अर्जेंटीना के डिफेंडर लिसांद्रो मार्टिनेज ने सोशल मीडिया पर भावुक संदेश साझा करते हुए प्रशंसकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि फाइनल का परिणाम टीम की पूरी यात्रा को परिभाषित नहीं करता और पूरी टीम को अपने प्रदर्शन पर गर्व है।विश्व कप खिताब बचाने उतरी अर्जेंटीना की टीम को फाइनल में स्पेन के खिलाफ अतिरिक्त समय में 0-1 से हार का सामना करना पड़ा।

मार्टिनेज ने एक्स पर लिखा, हम सभी जिस ट्रॉफी के हकदार थे, उसे घर नहीं ला पाने का दर्द दिल में है, लेकिन इस जर्सी, अपने साथियों, कोचिंग स्टाफ, अधिकारियों, मेडिकल टीम, रसोइयों, किट स्टाफ और उन सभी लोगों पर मुझे बेहद गर्व है, जिन्होंने इस अभियान को सफल बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। सबसे बढ़कर उन प्रशंसकों का धन्यवाद, जिन्होंने हमें अपना प्यार, ताकत और जुनून दिया। यही एकता हमेशा बनी रहे, यही मेरी कामना है। उन्होंने विश्व कप जीतने पर स्पेन को भी बधाई दी। मार्टिनेज ने कहा, स्पेन को इस शानदार और पूरी तरह से योग्य खिताब के लिए बधाई।

अर्जेंटीना की विश्व कप यात्रा पर विचार करते हुए मार्टिनेज ने कहा कि टीम ने कई मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन कभी बहाने नहीं बनाए।उन्होंने लिखा, मैं अपने देशवासियों से कहना चाहता हूं कि केवल अंतिम परिणाम से हमारी पूरी यात्रा का मूल्यांकन न करें। हमने कई चुनौतियों का सामना किया, असंभव को संभव बनाया और कभी बहाने नहीं ढूंढ़े, बल्कि आगे बढ़ने के कारण तलाशे। हमने मैदान के अंदर और बाहर पूरे सम्मान

के साथ अपने देश के रंगों की रक्षा की। अपने परिवारों और करोड़ों अर्जेंटीनी प्रशंसकों के साथ बिताए ये पल हमेशा यादगार रहेंगे। आप सभी का प्रतिनिधित्व करना हमारे लिए हमेशा गर्व की बात रहेगी।

अपने संदेश के अंत में मार्टिनेज ने लिखा, आप सभी का दिल से धन्यवाद। आइए, अपने देश का ख्याल रखें। अर्जेंटीना, मैं तुमसे प्यार करता हूं।

एफआईएच यूथ हॉकी5एस एशियाई चैंपियनशिप: भारत की पुरुष और महिला टीमें अपराजेय

एजेंसी

मस्कट (ओमान)। एफआईएच यूथ हॉकी5एस एशियाई चैंपियनशिप 2026 में भारतीय सब-जूनियर पुरुष और महिला टीमों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। एलीट पूल मुकाबलों में पुरुष टीम ने मेजबान ओमान और चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को हराया, जबकि महिला टीम ने चीन के साथ मुकाबला ड्रॉ खेलने के बाद उज्बेकिस्तान को एकतरफा अंदाज में शिकस्त दी।

भारतीय सब-जूनियर पुरुष टीम ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 7-4 से पराजित किया। भारत की ओर से करण गौतम ने 5वें, 9वें और 19वें मिनट में गोल दागकर हैट्रिक पूरी की। इसके अलावा राहुल यादव (3'), प्रह्लाद राजभर (10'), कप्तान केतन कुशवाहा (11') और रोमित पाल (11') ने एक-एक गोल किया।पाकिस्तान के लिए असलम मुहम्मद फरहान (6'), अदील (8') और उस्मान मुहम्मद (10',

16') ने गोल किए।

इससे पहले भारतीय पुरुष टीम ने मेजबान ओमान को 14-0 से करारी शिकस्त दी। कप्तान केतन कुशवाहा ने चार गोल (6', 11', 15', 20') दागे, जबकि आशीष तानी पूर्ति ने (1', 16', 19') हैट्रिक बनाई। राहुल यादव (2', 12') और शाहरुख अली (3', 13') ने दो-दो गोल किए। वहीं प्रह्लाद राजभर (9'), करण गौतम (15') और रोमित पाल (18') ने भी गोल कर भारत की बड़ी जीत में योगदान दिया।वहीं, भारतीय सब-जूनियर महिला टीम ने अपने दूसरे एलीट पूल मुकाबले में चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। चीन के लिए चेन गे ने चौथे मिनट में बढ़त दिलाई। इसके बाद नौशीन नाज ने 16वें और 17वें मिनट में लगातार दो गोल कर भारत को बढ़त दिला दी। हालांकि, जियाक्सिन गुओ ने 19वें मिनट में बराबरी का गोल कर मुकाबला ड्रॉ करा दिया। दिन के दूसरे मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को 16-0 से रौंद दिया। नौशीन नाज ने चार गोल (6', 9', 15', 16') किए, जबकि संदीपा कुमारी (2', 6', 20') और कप्तान स्वीटी कुजूर (10', 13', 20') ने हैट्रिक जमाई। दिया (3', 17') और पुष्पा मांझी (11', 13') ने दो-दो गोल किए। इसके अलावा किरण एक्का (8') और नीलम टोपनो (18') ने भी गोल दागे।

जूडो महाकुंभ स्टेट चैंपियनशिप में पदक जीत लौटे खिलाड़ियों का अभिनंदन

एजेंसी

मुरादाबाद। लखनऊ में 15 से 20 जुलाई तक आयोजित जूडो महाकुंभ स्टेट चैपियनशिप-2026 में शानदार प्रदर्शन कर पदक जीतने वाले आरएसडी स्पोर्ट्स एकेडमी मुरादाबाद के खिलाड़ियों का स्वागत अभिनंदन हुआ। आरएसडी स्पोर्ट्स एकेडमी मुरादाबाद के निदेशक डा. विनोद कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में एकेडमी की अन्वी सक्सेना ने 30 किग्रा भार वर्ग में कांस्य पदक, अधीरा टंडन ने 48 किग्रा भार वर्ग में कांस्य पदक तथा ख्याति सिंह ने 70 किग्रा से अधिक भार वर्ग में रजत पदक जीतकर अकादमी एवं जनपद का नाम रोशन किया। तीनों खिलाड़ी जूडो कोच मयंक कश्यप के मार्गदर्शन में नियमित रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस शानदार

प्रदर्शन पर निदेशक डा. विनोद कुमार, डा. जी. कुमार, डा. गौरव कुमार, डा. गरिमा शर्मा, डा. अजय शर्मा, बास्केटबाल कोच मोहित चौधरी तथा स्केटिंग कोच शहवाज़ अली ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों एवं जूडो कोच मयंक कश्यप को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि उनकी यह सफलता अन्य खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणास्त्रोत बनेगी।

मेक्सिको के दिग्गज गोलकीपर गुइलेर्मो ओचोआ ने लिया संन्यास, 22 साल के करियर का हुआ अंत

एजेंसी

मेक्सिको सिटी। मेक्सिको के महान गोलकीपरों में शुमार गुइलेर्मो ओचोआ ने पेशेवर फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी। 41 वर्षीय ओचोआ ने अपने 22 साल लंबे शानदार करियर को अलविदा कहा। उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि फीफा विश्व कप 2026 उनके करियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा। हालांकि इसके बाद उनके किसी नए क्लब से जुड़ने की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन अब उन्होंने उन सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया है।सोशल मीडिया पर भावुक संदेश साझा करते हुए ओचोआ ने कहा, मैंने अपना सबकुछ झोंक दिया। अपने क्लबों और राष्ट्रीय टीम के लिए मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और आज मैं अपने गोलकीपिंग ग्लव्स उतार रहा हूं। गोलकीपर होना यह जानना है कि शायद 90 मिनट तक आपको सिर्फ

एक ही मौका मिले, जब सब कुछ आप पर निर्भर हो। और जब वह पल आए तो आप हिचकिचा नहीं सकते।

ओचोआ मेक्सिको की ओर से छह फीफा विश्व कप की टीम में शामिल होने वाले खिलाड़ियों में रहे। यह उपलब्धि केवल क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी जैसे महान खिलाड़ियों के नाम भी दर्ज है। उन्होंने 2014 (ब्राजील), 2018 (रूस) और 2022 (कतर) विश्व कप में मेक्सिको के प्रथम पसंद गोलकीपर के रूप में जिम्मेदारी निभाई।ओचोआ ने फरवरी 2004 में क्लब अमेरिका के लिए अपना पेशेवर पदार्पण किया। सात सीजन तक क्लब अमेरिका के लिए खेलने के बाद वह 2011 में फ्रांस के अजाक्सियो क्लब से जुड़े और यूरोप में खेलने वाले मेक्सिको में जन्मे पहले गोलकीपर बने। इसके बाद उन्होंने मालागा, ग्रेनाडा, स्टैंडर्ड लीज, सालेरनिताना, एवीएस फुटबोल और एईएल लिमासोल जैसे क्लबों का भी प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 2019 से 2022 के बीच उन्होंने क्लब अमेरिका में वापसी भी की। अपने विदाई संदेश में ओचोआ ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक सपना मुझे इतनी दूर तक ले जाएगा। आज मैं गर्व के साथ पीछे मुड़कर देख सकता हूं और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं–धन्यवाद। मैं अपने साथ करोड़ों लोगों का प्यार और यह संतोष लेकर जा रहा हूं कि मैंने मेक्सिको के लिए अपना सबकुछ दिया। विश्व कप 2026 में वह मुख्य रूप से राउल रेंगेल के बैकअप गोलकीपर रहे, लेकिन मुख्य कोच जेवियर अगुइरे ने चेक गणराज्य के खिलाफ अंतिम ग्रुप मैच में उन्हें आखिरी 13 मिनट खेलने का मौका दिया। मुकाबले के बाद भावुक ओचोआ ने एस्टाडियो एज़्टेका के गोलपोस्ट को चूमा, जहां से उनके करियर की शुरुआत हुई थी।

सिडनी सिक्सर्स के मुख्य कोच बने मैथ्यू मॉट, दो साल का करार

एजेंसी

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी कोच मैथ्यू मॉट को बिग बैश लीग (बीबीएल) फ्रेंचाइजी सिडनी सिक्सर्स की पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। 52 वर्षीय मॉट के साथ फ्रेंचाइजी ने दो साल का अनुबंध किया है। वह बीबीएल-16 से पहले यह जिम्मेदारी संभालेंगे। मॉट ने जेम्स होप्स की जगह ली है, जिन्होंने पिछले महीने क्वींसलैंड और ब्रिस्बेन हीट के साथ दोहरी कोचिंग भूमिका स्वीकार करने के बाद पद छोड़ दिया था। मैथ्यू मॉट पिछले दो सीजन से सिडनी सिक्सर्स की पुरुष टीम के सहायक कोच थे। इसके बाद उन्होंने पिछले सीजन महिला टीम की कमान संभाली और टीम को डब्ल्यूबीबीएल चैलेंजर तक पहुंचाया। सिडनी सिक्सर्स इस सप्ताह महिला टीम के नए मुख्य कोच की घोषणा करेगी। मैथ्यू मॉट का कोचिंग करियर दो दशक से अधिक लंबा और बेहद सफल रहा है। उन्होंने 2022 से 2024 तक इंग्लैंड की पुरुष सीमित ओवर टीम के मुख्य कोच के रूप में कार्य किया और जोस बटलर की कप्तानी में टीम को 2022 टी20 विश्व कप का खिताब दिलाया। इससे पहले वह 2015 से 2022 तक ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के मुख्य कोच रहे, जहां उनके मार्गदर्शन में टीम ने दो टी20 विश्व कप, 2022 महिला वनडे विश्व कप, चार एशेज सीरीज जीतीं और लगातार 26 वनडे मैच जीतने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। नियुक्ति के बाद मैथ्यू मॉट ने फ्रेंचाइजी की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा, मैं लंबे समय से सिक्सर्स परिवार का हिस्सा रहा हूं। ऐसे में बीबीएल टीम का मुख्य कोच बनने का अवसर मिलना मेरे लिए बेहद उत्साहजनक है। यह क्लब शानदार इतिहास और विजेता संस्कृति वाला है। मैं उन मजबूत नींवों को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूं, जो पिछले कई वर्षों में तैयार की गई हैं। पुरुष टीम के साथ काम करते हुए मैंने खिलाड़ियों की प्रतिभा और क्षमता को करीब से देखा है। उन्होंने आगे कहा, यह जरूर निराशाजनक है कि मैं अब डब्ल्यूबीबीएल टीम का मुख्य कोच नहीं रहूंगा, लेकिन महिला टीम के साथ बिताया समय मेरे लिए बेहद खास रहा।

वॉर्नर ने कबूली सिडनी में शराब पीकर गाड़ी चलाने की बात, अगली सुनवाई में कोर्ट सुनाएगा सजा

एजेंसी

सिडनी । ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर ने बुधवार को सिडनी की एक कोर्ट में शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस मामले में कोर्ट 18 अगस्त को सजा सुनाएगा। ऑस्ट्रेलिया की घरेलू टी20 लीग बिग बैश (बीबीएल) में सिडनी थंडर फ्रेंचाइजी की कमान संभाल रहे वॉर्नर कोर्ट की कार्रवाई के दौरान खुद पेश नहीं हुए। इसके बजाय, डेविड वॉर्नर की ओर से उनके वकील बॉबी हिल सिडनी की अदालत में पेश हुए और उन्होंने शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में औपचारिक रूप से अपना दोष स्वीकार किया। यह मामला 5 अप्रैल, ईस्टर रविवार का है, जब वॉर्नर एक वैन चला रहे थे। वह एक जगह पर रुके, जो यादृच्छिक श्वास परीक्षण बिंदु से थोड़ी दूरी पर थी, जिसके बाद यह मामला सामने आया। इसके बाद पुलिस ने सड़क किनारे उनका श्वास टेस्ट किया। जांच में उनके शरीर में अल्कोहल की मात्रा तय कानूनी सीमा से दोगुनी से भी ज्यादा पाई गई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए थाने ले गई। वॉर्नर के वकील बॉबी हिल ने इस साल की शुरुआत में एक सुनवाई के दौरान कहा था, 'हम में से बहुत से लोग ऐसे गलत फैसले लेते हैं। मुझे लगता है कि उन गलत फैसलों को मानना ??और उनके लिए जवाबदेह होना जरूरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक ट्रेड्समैन हैं, एक डॉक्टर हैं या दुनिया के सबसे अच्छे ओपनिंग बैट्समैन में से एक है।

विश्व कप जीतकर 51 साल का इंतजार खत्म करना चाहते हैं: हरमनप्रीत

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा है कि टीम का लक्ष्य 51 वर्षों से चले आ रहे एफआईएच हॉकी विश्व कप खिताब के इंतजार को खत्म कर इतिहास रचना है। उन्होंने विश्वास जताया कि अनुभवी और युवा खिलाड़ियों के संतुलित संयोजन वाली भारतीय टीम विश्व कप में किसी भी प्रतिद्वंद्वी को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

बेल्जियम और नीदरलैंड की संयुक्त मेजबानी में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 में भारत को पूल-डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगी। हरमनप्रीत दूसरी बार विश्व कप में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इससे पहले भारत के एकमात्र विश्व कप विजेता कप्तान अजित पाल सिंह ने भी दो बार टीम का नेतृत्व किया था। उनके नेतृत्व में भारत ने 1971 में कांस्य और 1975 में विश्व कप खिताब जीता था, जो अब तक भारत का एकमात्र विश्व कप स्वर्ण है। हरमनप्रीत ने हॉकी इंडिया के हवाले से कहा, पेरिस ओलंपिक 2024 में लगातार दूसरा कांस्य पदक जीतने के बाद टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। प्रो लीग के अंतिम चरण में हमारे प्रदर्शन ने दिखाया कि हम लगातार बेहतर हो रहे हैं। हमारी तैयारी अच्छी चल रही है और हम विश्व कप के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में निरंतरता सबसे अहम होती है। उन्होंने कहा, हमें हर मैच में बेहतर प्रदर्शन करना होगा, अपनी योजनाओं पर कायम रहना होगा और छोटी-छोटी गलतियों से बचना होगा। विश्व कप में हर अवसर का पूरा फायदा उठाना जरूरी है। टीम की सबसे बड़ी चुनौती पर हरमनप्रीत ने कहा कि स्ट्राइकिंग सर्कल में आक्रामक और रक्षात्मक दोनों परिस्थितियों में प्रभावी प्रदर्शन करना बेहद महत्वपूर्ण होगा।

उन्होंने कहा, हमारा पूरा ध्यान इस बात पर है कि सर्कल में मिले हर मौके, चाहे वह पेनल्टी कॉर्नर हो, गोल पर शॉट हो या अटैकिंग मूव, उसका अधिकतम लाभ उठाया जाए। अनुभवी और युवा खिलाड़ियों के संयोजन पर उन्होंने कहा, टीम का संतुलन बहुत अच्छा है। हाल के मुकाबलों में हमने दुनिया की मजबूत टीमों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है। अनुभवी खिलाड़ी युवा खिलाड़ियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और सभी का लक्ष्य एक ही है– विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना।

कप्तानी के दबाव पर हरमनप्रीत ने कहा, मेरे लिए बड़े टूर्नामेंट में पदक जीतना हमेशा व्यक्तिगत उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण रहा है। 250 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलना गर्व की बात है, लेकिन टीम की सफलता ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को सलाह देते हुए कहा, मैं हमेशा उन्हें बिना किसी दबाव के खुलकर खेलने के लिए कहता हूं। गलती होने से ज्यादा जरूरी है कि आप उस पर तुरंत प्रतिक्रिया दें और टीम के लिए लड़ते रहें। अभ्यास में जो तैयारी करते हैं, वही मैच में दिखाई देती है।

भारत और पाकिस्तान एक ही पूल में हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत पाकिस्तान से नहीं हारा है, लेकिन इस मुकाबले को लेकर हमेशा अलग उत्साह रहता है। हरमनप्रीत ने कहा, हर कोई इस मैच का इंतजार कर रहा है और सभी को उम्मीद है कि हम जीतेंगे लेकिन हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा और समझदारी से खेलना होगा। हमारे लिए वेल्स, इंग्लैंड और पाकिस्तान– तीनों मुकाबले समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। पहले मिनट से ही हमें विपक्षी टीम पर दबाव बनाना होगा और मिले मौकों को गोल में बदलना होगा। भारतीय कप्तान ने प्रशंसकों से टीम का समर्थन जारी रखने की अपील करते हुए कहा, हमने टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद पदक जीतकर नई उम्मीद जगाई थी।

बिना इंटरनेट और क्यूआर कोड के अब फटाफट होगा यूपीआई पेमेंट, एनपीसीआई ला रहा नया 'टैप-टू-पे' फीचर

हैदराबाद। भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने के लिए एनपीसीआई (NPCI) एक क्रांतिकारी 'टैप-टू-पे' तकनीक पर काम कर रहा है। इस नई सुविधा के आने से उपयोगकर्ताओं को बेसमेंट, फ्लाइट या अंडरग्राउंड मेट्रो जैसे कम नेटवर्क वाले क्षेत्रों में भी बिना इंटरनेट के आसानी से यूपीआई पेमेंट करने की सुविधा मिलेगी। यह आगामी फीचर एनएफसी (नियर-फील्ड कम्युनिकेशन) तकनीक पर आधारित होगा, जिससे पेमेंट करने के लिए किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए ग्राहकों को अपने यूपीआई लाइट वॉलेट में पहले से पैसे जोड़ने होंगे, जिसके बाद वे बिना इंटरनेट के सीधे पीओएस मशीन से फोन को टैप करके ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। शुरुआती चरण में इस ऑफलाइन तकनीक के माध्यम से बिना यूपीआई पिन दर्ज किए एक बार में अधिकतम 2,000 रुपये तक का भुगतान किया जा सकेगा। फिलहाल यह फीचर विकास और परीक्षण के चरण में है, और एनपीसीआई द्वारा इसके आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने के बाद डिजिटल भुगतान का अनुभव पूरी तरह बदल जाएगा।

अर्बन चैलेंज फंड के तहत 31,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी: डी. थारा

नई दिल्ली। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अर्बन चैलेंज फंड के दिशा-निर्देश अंतिम रूप दिए जाने के महज 20 से 25 दिनों के भीतर 31,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। यह जानकारी मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव डी. थारा ने उद्योगमंडल फिक्की के नौवें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन समिट के दौरान यहां दी। सुश्री थारा ने बताया कि अब तक स्वीकृत परियोजनाओं के वित्तपोषण में 44 प्रतिशत हिस्सा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का है, जबकि 22 प्रतिशत निवेश सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीवी) के माध्यम से आ रहा है। इसके अलावा 5 से 7 प्रतिशत धनराशि बॉन्ड्स के जरिए जुटाई जा रही है, जबकि शेष वित्तपोषण वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (हडको) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ ने कहा कि भारत के शहर देश की केवल 3 प्रतिशत भूमि पर बसे होने के बावजूद 60 से 70 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि अर्बन चैलेंज फंड सब्सिडी-आधारित योजनाओं से हटकर चुनौती-आधारित मॉडल की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। इस योजना के तहत वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक वहन कर सकती है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें समान रूप से योगदान देंगी, जबकि शेष राशि ऋणदाताओं और निजी निवेशकों (प्राइवेट इक्विटी) से जुटाई जाएगी।

बंधन बैंक का कारोबार पहली तिमाही में 11 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में बंधन बैंक का कारोबार 11 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 3.2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया। बंधन बैंक ने बताया कि कुल जमा राशि में खुदरा जमा का हिस्सा अब लगभग 74 फीसदी है। बैंक का कहना है कि वित्त वर्ष 2026-27 में कारोबार में यह बढ़ोतरी बढ़ते वितरण नेटवर्क, बेहतर परिचालन दस्ता और उत्कर्षता की दिशा में निरंतर प्रयास का परिणाम है। पहली तिमाही में बैंक का शुद्ध मुनाफा 502 करोड़ रुपये रहा।देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 35 में बंधन बैंक के लगभग 6,400 बैंकिंग आउटलेट और 3.2 करोड़ ग्राहक हैं। बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 74,500 से ज़्यादा है। बैंक के पास जमा राशि तिमाही के दौरान सालाना सात प्रतिशत बढ़कर 1.65 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसी अवधि में बैंक द्वारा दी गयी कुल उधारी 1.56 लाख करोड़ रुपये पर रही। कुल जमा में चालू खाता और बचत खाता (कासा) का अनुपात 29.4 प्रतिशत रहा। वित्तीय स्थिरता के एक अहम पैमाना माना जाने वाला बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 18.2 प्रतिशत पर है।

'कनाडाई हितों की रक्षा के लिए करेंगे सभी उपाय ', अमेरिकी आयात शुल्क पर कार्नी का बयान

नई दिल्ली। अमेरिका द्वारा ज्यादातर कनाडाई उत्पादों पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की घोषणा के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि उनकी सरकार अपने लोगों और कारोबारियों के हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी उपाय करेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को तीन प्रशासनिक आदेशों पर हस्ताक्षर किये। इनके जरिये कनाडा से आयात होने वाले लगभग सभी उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। व्हाइट हाउस द्वारा जारी फैक्टशीट में कहा गया है कि कनाडा द्वारा अमेरिका में बने वाहनों पर लगाये गये ऊंचे शुल्क के जवाब में अमेरिका ने आयात शुल्क बढ़ाये हैं। आदेश के अनुसार, नये शुल्क 19 अगस्त से प्रभावी होंगे। इस आदेश के दायरे से ऊर्जा, पोटाश और सेक्शन 232 के तहत आने वाले उत्पादों को बाहर रखा गया है। साथ ही मछली और महत्वपूर्ण खनिजों को भी अतिरिक्त शुल्क से छूट दी गयी है। श्री कार्नी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा है कि अमेरिका का यह कदम कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको के बीच मुक्त व्यापार संधि का उल्लंघन है। उन्होंने कहा है कि हर हाल में अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और कनाडाई कामगारों, किसानों, कारोबारियों तथा परिवारों के समर्थन के लिए कनाडा सभी आवश्यक उपाय करेगा।

पाकिस्तान सरकार ने डीजल की कीमत में की 5.71 रुपए की बढ़ोतरी, पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की गिरावट

एजेंसी

इस्लामाबाद । पाकिस्तान की केंद्र सरकार ने एक दिन के लिए हाई-स्पीड डीजल की कीमत में 5.71 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे प्रति लीटर की कमी का ऐलान किया। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के फैसले के बाद एचएसडी की कीमत 360.06 पीकेआर (पाकिस्तानी रुपए) प्रति लीटर हो गई, जबकि पेट्रोल की कीमत पीकेआर 315.8 प्रति लीटर है। पाकिस्तान सरकार ने फैसला किया है कि पश्चिम एशिया में नए तनाव के बाद अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण फ्यूल की कीमतें रोजाना तय की जाएंगी। पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा लागू की गई रोजाना की कीमतें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ग्लोबल मार्केट की कीमतों के सात-

दिन के हफ्ते के औसत पर आधारित हैं। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी अपनी वेबसाइट पर हर दिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें अपडेट करेगी ताकि पारदर्शिता रहे और अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर कंज्यूमर्स तक पहुंचे। पिछले हफ्ते, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए और माल ढुलाई के चार्ज बढ़ा दिए गए थे और पाकिस्तान की केंद्र सरकार की फ्यूल की कीमतों में बार-बार बदलाव की पॉलिसी के बाद पेट्रोल पंप ऑपरेटरों ने देश भर में हड़ताल की धमकी दी थी। पाकिस्तान सरकार के 17 जुलाई को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने के बाद, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों ने तुरंत असर से किराए में बदलाव किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 15 से 17 फीसदी की बढ़ोतरी की गई, जबकि गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों ने माल ढुलाई के चार्ज में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा है कि जब भी फ्यूल की कीमतें बढ़ेंगी, तो किराए में भी बदलाव किया जाएगा। ऑफिस में काम करने वालों और स्टूडेंट्स के लिए पिक एंड ड्रॉप सर्विस ने घोषणा की है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव के हिसाब से उनके चार्ज बदल जाएंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कम से कम स्टॉप-टू-स्टॉप किराया बढ़ाकर पीकेआर 60 कर दिया गया है।

लंबी दूरी के ट्रांसपोर्टरों ने अपने टैरिफ बढ़ा दिए हैं, कराची और पेशावर के बीच कंटेनर, ट्रेलर और व्हीलर ट्रांसपोर्ट का फ्रेट चार्ज कथित तौर पर बढ़कर 800,000 पीकेआर हो गया है।

पेटीएम ने पेश किए साल 2026 की पहली तिमाही के शानदार नतीजे, कुल कमाई 28फीसदी बढ़कर 2,448 करोड़ रुपये पर पहुंची

एजेंसी

नई दिल्ली। देश की प्रमुख डिजिटल पेमेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस (पेटीएम) ने वर्ष 2026 की पहली तिमाही के बेहद मजबूत वित्तीय नतीजे जारी किए हैं। मर्चेंट बिजनेस और लोन वितरण में हुई जबरदस्त वृद्धि के दम पर कंपनी ने कामकाज के मोर्चे पर अब तक का रिकॉर्ड 203 करोड़ रुपये का तिमाही मुनाफा दर्ज किया है।

राजस्व और वित्तीय आंकड़ों में भारी उछाल

जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कंपनी का कुल राजस्व 28 प्रतिशत की जोरदार तेजी के साथ 2,448 करोड़ रुपये हो गया है। इसके अलावा, टैक्स भुगतान के बाद शुद्ध मुनाफा 79 प्रतिशत बढ़कर 220 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति बेहद मजबूत हुई है।

साउंडबॉक्स और यूपीआई ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी

व्यापारियों के बीच पेटीएम के साउंडबॉक्स और पीओएस मशीनों

की संख्या 1.57 करोड़ के पार पहुंच गई है, जबकि यूपीआई लेन-देन में भी 45 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। मजबूत कैश रिजर्व के साथ कंपनी डिजिटल पेमेंट सेक्टर में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है।

कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स का आईपीओ 146.64 गुना हुआ सब्सक्राइब

एजेंसी

नई दिल्ली। कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को बोली के तीसरे एवं अंतिम दिन 146.64 गुना सब्सक्राइब किया गया।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के आंकड़ों के मुताबिक इस आईपीओ के तहत की गई 78,35,821 शेयरों की पेशकश के मुकाबले 114,90,37,400 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं है। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों की श्रेणी को 267.36 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जबकि पात्र संस्थागत खरीदारों के खंड को 240.7 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। वहीं, खुदरा निवेशकों के खंड को 41.15 गुना अभिदान मिला। इसके पहले कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने गुरुवार को एंकर निवेशकों से 135 करोड़ रुपये जुटाए। इस आईपीओ के तहत 400 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों का ताजा निर्गम और प्रवर्तकों द्वारा 50 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) इसमें शामिल

थी। कंपनी ने आईपीओ के लिए 402-424 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में गठित कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स एकीकृत खनन सेवा प्रदाता कंपनी है। इसकी अपनी कोई खदान नहीं है लेकिन ये अपने ग्राहकों को खनन और लॉजिस्टिक्स सेवाएं देती है। यह कंपनी 1,911 गाड़ियों, प्लांट और मशीनरी का बेड़ा चलाती है। इसके अलावा ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडियरी समेत कई ग्राहकों को सर्विस देती है।

सब्सक्रिप्शन के लिए खुला श्री बालाजी माला टेक्सटाइल का आईपीओ, 29 जुलाई को हो सकती है लिस्टिंग

एजेंसी

नई दिल्ली। माला साड़ी ब्रांड की साड़ियों की निर्माता कंपनी श्री बालाजी (माला) टेक्सटाइल लिमिटेड का 18.90 करोड़ रुपये का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस आईपीओ में 24 जुलाई तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद 27 जुलाई को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि 28 जुलाई को अलॉटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर 29 जुलाई को बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं। दोपहर 12:30 बजे तक ये आईपीओ 1.30 गुना सब्सक्राइब हो चुका था।

इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 66 रुपये से लेकर 70 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 2,000 शेयर का है। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स को दो लॉट यानी 4,000 शेयरों के लिए बोली लगाना होगा, जिसके लिए उन्हें 2,80,000 रुपये का निवेश करना होगा। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 27 लाख नए शेयर जारी हो रहे हैं। इस आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए 47.19 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इसके अलावा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए 33.33 प्रतिशत हिस्सा और नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए 14.44 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। इसके अलावा मार्केट मेकर के लिए 5.04 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इस इश्यू के लिए जीवाईआर कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है। वहीं मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मार्केट मेकर है। श्री बालाजी (माला) टेक्सटाइल लिमिटेड की वित्तीय स्थिति की बात करें तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत मामूली उतार चढ़ाव के बावजूद मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी को 2.46 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 4.95 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। वहीं पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को 5.85 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ। इस दौरान कंपनी की राजस्व प्राप्ति में उतार चढ़ाव के बावजूद बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में इसे 195.89 करोड़ का कुल राजस्व प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 202-25 में घट कर 193.44 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को 212.40 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था।

महंगी होंगी मारुति सुजुकी की कारें, दो महीनों के भीतर कंपनी ने दूसरी बार किया कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला

एजेंसी

नई दिल्ली। यदि आप निकट भविष्य में देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी की कोई नई गाड़ी खरीदने का विचार बना रहे हैं, तो यह समाचार आपके लिए बेहद जरूरी है। वाहन निर्माता कंपनी ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा झटका देते हुए आगामी अगस्त महीने से अपनी सभी गाड़ियों की कीमतों में एक बार फिर इजाफा करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विभिन्न मॉडलों के आधार पर गाड़ियों के दामों में अधिकतम तीस हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले दो महीनों के भीतर यह दूसरा मौका है जब कंपनी अपने वाहनों की कीमतों को बढ़ाने जा रही है। उत्पादन लागत और कच्चे माल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि को इस फैसले का मुख्य कारण बताया गया है। कंपनी का कहना है कि पिछले कई महीनों से निर्माण से जुड़ी लागत लगातार बढ़ रही थी। हालांकि इस अतिरिक्त वित्तीय भार को कम करने के लिए आंतरिक स्तर पर कई आवश्यक कदम उठाए गए, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई और उत्पादन खर्च के दबाव के कारण अंततः कीमतों में बढ़ोतरी करना कंपनी के लिए अपरिहार्य हो गया। इसके साथ ही कंपनी ने यह आश्वासन भी दिया है कि इस मूल्य वृद्धि का

ग्राहकों पर कम से कम असर पड़े, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। यह पहला अवसर नहीं है जब इस वर्ष कंपनी ने अपने वाहनों के दाम बढ़ाए हैं। इससे ठीक पहले जून के महीने में भी कंपनी ने अपने लगभग सभी मॉडलों की कीमतों में तीस हजार रुपये तक की वृद्धि की थी। उस समय भी इस फैसले के पीछे निर्माण लागत का बढ़ना और महंगाई को ही मुख्य वजह बताया गया था। अब अगस्त महीने से प्रभावी होने वाली यह नई मूल्य वृद्धि जून में बढ़ाई गई कीमतों के ऊपर एक अतिरिक्त आर्थिक बोझ की तरह लागू होगी।

इस मूल्य वृद्धि का प्रभाव कंपनी के संपूर्ण उत्पाद पोर्टफोलियो पर समान रूप से देखने को मिलेगा। कंपनी के बेड़े में शामिल शुरुआती स्तर की छोटी गाड़ियों से लेकर प्रीमियम श्रेणी के बड़े वाहनों तक सभी की कीमतें बढ़ जाएंगी। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि अलग-अलग गाड़ियों के मॉडल और उनके वेरिएंट के हिसाब से बढ़ाई जाने वाली राशि भिन्न-भिन्न तय की जाएगी।

वाहन क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि जो उपभोक्ता आने वाले समय में नई गाड़ी खरीदने की योजना पर काम कर रहे हैं, उनके लिए अगस्त महीना शुरू होने से पहले ही बुकिंग अथवा खरीदारी की प्रक्रिया को पूरा कर लेना अत्यधिक फायदेमंद साबित हो सकता है। नए नियम लागू होने के बाद ग्राहकों को उसी पसंदीदा मॉडल को अपने घर लाने के लिए पहले की तुलना में अधिक धनराशि का भुगतान करना होगा। लगातार दूसरी बार की गई इस घोषणा से यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि वाहन निर्माण की बढ़ती हुई लागत का सीधा और सीधा असर अब आम कार खरीदारों की जेब पर पड़ने लगा है।

डॉलर की कमजोर मांग से रुपया 11 पैसे मजबूत

एजेंसी

मुंबई। अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर की मांग कमजोर रहने से रुपया 11 पैसे मजबूत हुआ और कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 96.25 रुपये का बोला गया। पिछले कारोबारी दिवस पर भारतीय मुद्रा छह पैसे टूटकर 96.36 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई थी। कच्चे तेल में तेजी से रुपया आज शुरू में दबाव में रहा। डॉलर की कमजोर मांग के कारण हालांकि बाद में इसका ग्राफ ऊपर की तरफ गया।रुपये की शुरुआत छह पैसे की गिरावट के साथ 96.42 रुपये प्रति डॉलर पर हुई और यही इसका दिवस का निचला स्तर रहा। बीच कारोबार में दोपहर बाद यह 96.13 रुपये प्रति डॉलर तक मजबूत हुआ। अंत में 96.25 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। लंदन का ब्रेंट क्रूड वायदा सवा दो प्रतिशत चढ़कर 91 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया। दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर सूचकांक भी 0.10 प्रतिशत मजबूत हुआ। इन दोनों कारकों से रुपये की बढ़त सीमित रही। विदेशी संस्थागत निवेशकों के भारतीय पूंजी बाजार में 26.9 करोड़ डॉलर का शुद्ध निवेश करने से भारतीय मुद्रा को समर्थन मिला।

सर्राफा बाजार में महंगा हुआ सोना, चांदी के भाव में मामूली गिरावट

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में आज शुरुआती कारोबार के दौरान सोने के भाव में तेजी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर, चांदी की कीमत में आज शुरुआती कारोबार के दौरान मामूली कमजोरी दर्ज की गई है। भाव में आए उछाल के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में सोना 700 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 760 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। वहीं चांदी के भाव में आज 200 रुपये प्रति किलोग्राम की सांकेतिक गिरावट नजर आ रही है।

भाव में आए उछाल के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,44,230 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,44,380 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 1,32,210 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,32,360 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में प्रति किलोग्राम 200 रुपये की गिरावट आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 2,34,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है।

दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 1,44,380 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,32,360 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,44,230 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,32,210 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,44,280 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,32,260 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,44,230 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,32,210 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,44,230 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,32,210 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,44,280 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,32,260 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,44,380 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,32,360 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,44,280 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,32,260 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,44,380 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,32,360 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी आज सोने के भाव में तेजी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 1,44,230 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

हेवीवेट शेयरों की बिकवाली से शेयर बाजार लाल निशान में बंद, सेंसेक्स-निफ्टी लुढ़के

एजेंसी

नई दिल्ली। एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे हेवीवेट शेयरों में हुई जोरदार बिकवाली ने आज घरेलू शेयर बाजार को पूरी तरह से झकझोर दिया। आज के कारोबार की शुरुआत मामूली कमजोरी के साथ हुई थी। दिन के कारोबार में लगातार उतार-चढ़ाव होता रहा, जिसमें बिकवालों का पलड़ा ज्यादातर समय भारी बना रहा। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.31 प्रतिशत और निफ्टी 0.21 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई का सेंसेक्स आज 58.89 अंक की मामूली कमजोरी के साथ 77,649.63 अंक के स्तर पर खुला। कारोबार की शुरुआत होते ही बाजार में हो रही खरीद बिक्री की वजह से इस सूचकांक की चाल भी ऊपर नीचे होने लगी। खरीदारी के सपोर्ट से पहले 15 मिनट के कारोबार में ही सेंसेक्स उछल कर हरे निशान में 77,753.18 अंक तक पहुंच गया। इसके बाद बाजार में बिकवाली का दबाव बन गया। शेयरों की लगातार हो रही बिक्री की वजह से दोपहर एक बजे के करीब यह सूचकांक 371.19 अंक की कमजोरी के साथ 77,337.33 अंक के स्तर तक आ गया। इसके बाद खरीदारों ने एक बार फिर जोर लगाया, जिसके कारण सेंसेक्स दिन के निचले स्तर से 130 अंक से अधिक की रिकवरी कर 238.41 अंक की गिरावट के साथ 77,470.11 अंक के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स की तरह ही एनएसई के निफ्टी ने आज 22.45 अंक टूट कर 24,216.05 अंक के स्तर से कारोबार की शुरुआत की। बाजार खुलते ही खरीदारी का सपोर्ट मिलने पर यह सूचकांक 23.70 अंक की मजबूती के साथ 24,262.20 अंक के स्तर तक आ गया। इसके बाद बाजार में हेवीवेट शेयरों में लगातार बिकवाली होने लगी, जिससे निफ्टी की चाल में गिरावट आने लगी। लगातार हो रही बिकवाली की वजह से दोपहर एक बजे के करीब निफ्टी 102.85 अंक लुढ़क कर 24,135.65 अंक के स्तर पर पहुंच गया।

हवाई यात्रियों की संख्या जून में घटकर 1.34 करोड़ पर, स्पाइसजेट की बाजार हिस्सेदारी दो प्रतिशत से कम हुई

एजेंसी

नई दिल्ली।घरेलू विमान सेवा कंपनियों की उड़ानों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या जून में घटकर 1.34 करोड़ रह गयी है। साथ ही वित्तीय संकट से जूझ रही स्पाइसजेट की बाजार हिस्सेदारी घटकर दो प्रतिशत से कम रह गयी है। इस साल मई में एक करोड़ 53 लाख 90 हजार के मासिक रिकॉर्ड के बाद हवाई यात्रियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गयी है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी आंकड़ों में बताया गया है कि जून में एक करोड़ 34 लाख 64 हजार लोगों ने हवाई सफर किया। यह जून 2025 के एक करोड़ 36 लाख चार हजार की तुलना में 1.03 प्रतिशत कम है। मौजूदा कैलेंडर वर्ष के पहले छह महीने में जनवरी से जून के दौरान घरेलू विमान सेवा कंपनियों ने आठ करोड़ 64 लाख चार हजार यात्रियों को सेवा प्रदान की है। पिछले साल की समान अवधि की तुलना में यह 1.44 प्रतिशत अधिक है। साल 2025 की पहली छमाही में आठ करोड़ 51 हजार 74 लोगों ने हवाई सफर किया था। जून में इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी मई के 64.9 प्रतिशत से बढ़कर 66.3 प्रतिशत पर पहुंच गयी, यानी कुल यात्रियों में 66.3 प्रतिशत ने उसकी उड़ानों में सफर किया। वहीं, एयर इंडिया समूह की बाजार हिस्सेदारी 25.6 प्रतिशत से घटकर 23.9 प्रतिशत रह गयी। नवोदित विमान सेवा कंपनी अकासा एयर की बाजार हिस्सेदारी एक महीने पहले के 5.8 फीसदी से बढ़कर 6.4 फीसदी हो गयी।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में दो महीने के टॉप लेवल पर क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड 92.63 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंचा

एजेंसी

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ रहे तनाव खाड़ी देशों से कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होने की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग और तेज होने की आशंका के बीच ब्रेंट क्रूड आज दो महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया। आज ब्रेंट क्रूड ने तेजी दिखाते हुए 92 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर लिया। इसी तरह वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड भी आज एक बार फिर 85 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ने आज 0.45 डॉलर प्रति बैरल की मामूली उछाल के साथ 91.46 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से कारोबार की शुरुआत की। ट्रेडिंग शुरू होने के बाद इसकी कीमत उछल कर 92.63 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में पिछले दो महीने के दौरान ब्रेंट क्रूड का ये सबसे ऊंचा स्तर है। हालांकि दिन के कारोबार में इसकी कीमत में मामूली गिरावट भी आई। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 11:30 बजे अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 1.34 डॉलर प्रति बैरल यानी 1.48 प्रतिशत की तेजी के साथ 92.25 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा था।

इसी तरह वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड ने आज सिर्फ 0.15 डॉलर प्रति बैरल की सामान्य बढ़त के साथ 84.59 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से आज के कारोबार की शुरुआत की। थोड़ी देर बाद ही डब्ल्यूटीआई क्रूड उछल कर 85.75 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि बाद में इसकी कीमत में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 11:30 बजे अंतरराष्ट्रीय बाजार में डब्ल्यूटीआई क्रूड 1.23 डॉलर प्रति बैरल यानी 1.46 प्रतिशत की तेजी के साथ 85.57 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा था। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर खत्म होने और पश्चिम एशिया में युद्ध तेज हो जाने की वजह से कच्चे तेल की कीमत में लगातार तेजी का रुख बना हुआ है। पिछले सप्ताह अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 87 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर एक महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। इसी तरह डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 81 डॉलर प्रति बैरल के स्तर के ऊपर चला गया था। इसके बाद ती दिन तक सुस्ती का माहौल बना रहा, लेकिन पिछले चार ट्रेडिंग सेशन से कच्चे तेल की कीमत में एक बार फिर तेजी का रुख बन गया है, जिसकी वजह से आज इसने पिछले दो महीने के सबसे ऊंचे स्तर को पार कर लिया है। जानकारों का कहना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ रहे तनाव की वजह से एक बार फिर कच्चे तेल की सप्लाई पर संकट बढ़ाने की आशंका बन गई है। टीएनवी फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ तारकेश्वर नाथ वैष्णव का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग लगातार तेज हो रही है। दोनों पक्षों की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं। इस बीच ईरान की ओर हूती विद्रोहियों ने भी मोर्चा संभालने का ऐलान कर दिया है। हूती विद्रोहियों ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका की ओर हो रहे हमले नहीं रुके तो वे रेड सी और बाब अल मंडेब जलडमरूमध्य के रास्ते जहाजों की होने वाली आवाजाही को ठप कर देंगे। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर मैरीटाइम बैन भी लगा दिया है और शिप ओनर्स को सऊदी के बंदरगाहों पर नहीं आने की धमकी भी दी है। वैष्णव का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य पहले से ही ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में अब अगर रेड सी और बाब अल मंडेब से भी जहाजों की आवाजाही रुक जाती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित होगी।

न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी का यू-टर्न, बोले-नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं

एजेंसी

वॉशिंगटन । न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी ने कहा कि सिटी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट के तहत इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ़्तार नहीं कर सकता। कानूनी समीक्षा में यह निष्कर्ष निकलने के बाद कि उनके प्रशासन के पास कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, उन्होंने अपने चुनावी वादे से पीछे हटते हुए यह बात कही। हालांकि, ममदानी ने नेतन्याहू को 'युद्ध अपराधी' कहा और ट्रम्प प्रशासन से आग्रह किया कि वे सितंबर में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के लिए न्यूयॉर्क आने पर उन्हें गिरफ्तार करें। ममदानी ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, 'मेरे प्रशासन ने लागू कानून के तहत उपलब्ध हर रास्ते की समीक्षा की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू यहां आते हैं तो क्या न्यूयॉर्क

शहर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के गिरफ़्तारी वारंट को लागू कर सकता है।' उन्होंने कहा, 'यह स्पष्ट है कि हमारे पास इस वारंट को लागू करने का स्वतंत्र कानूनी अधिकार नहीं है। ममदानी ने कहा कि संघीय सरकार के पास ऐसा अधिकार है और उन्होंने वॉशिंगटन से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में शामिल होने और उसके वारंट को लागू करने का आह्वान किया। अमेरिका इस कोर्ट का सदस्य नहीं है। मेयर की यह घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा यह कहे जाने के एक दिन बाद आई कि नेतन्याहू को उनकी अमेरिकी यात्रा के दौरान हिरासत में नहीं लिया जाएगा।

ट्रम्प ने सोमवार को ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा, 'संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू को किसी भी तरह से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।'

अपने मेयर पद के चुनाव अभियान के दौरान, ममदानी ने बार-बार कहा था कि जब इजराइली नेता न्यूयॉर्क आएंगे तो वे नेतन्याहू की गिरफ्तारी का आदेश देंगे। उन्होंने हाल ही में 'द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन' को बताया था कि उनका प्रशासन वारंट को लागू करने के बारे में शहर के कानून विभाग के साथ सक्रिय बातचीत कर रहा था। कानूनी निष्कर्ष के बावजूद ममदानी ने नेतन्याहू की आलोचना जारी रखी।

उन्होंने कहा, 'बेंजामिन नेतन्याहू एक युद्ध अपराधी हैं। फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ भयानक नरसंहार के सूत्रधार हैं।'

ममदानी ने आगे कहा, 'जैसा कि मैंने कहा है, मैं आईसीसी की इस बात से सहमत हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके अपराधों के लिए उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जैसा कि मैं आईसीसी द्वारा आरोपित किसी भी अन्य व्यक्ति के मामले में मानता हूं।'

ईरान मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन घिरा, अमेरिकी सीनेट ने युद्ध अधिकारों पर उठाए सवाल

एजेंसी

वॉशिंगटन । ईरान के खिलाफ दोबारा सैन्य कार्रवाई के बाद ट्रंप प्रशासन के फैसलों पर अमेरिकी सीनेट में दोनों दलों के सांसदों ने सवाल उठाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 87.6 अरब डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग मांगी है, लेकिन इससे दोनों पार्टियों (रिपब्लिकन और डेमोक्रेट) के सांसदों में नाराजगी देखी गई है। सीनेट की एप्रोप्रिएशन कमेटी की सुनवाई के दौरान रिपब्लिकन सीनेटर लिसा मर्कोव्स्की ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 87.6 अरब डॉलर के अतिरिक्त बजट प्रस्ताव पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विशेष मंजूरी के बिना 28 फरवरी को सैन्य कार्रवाई शुरू हो गई थी। 'युद्ध अधिकार प्रस्ताव' के तहत राष्ट्रपति को आम तौर पर 60 दिनों के भीतर लड़ाई खत्म करनी होती है, जब तक कि कांग्रेस सैन्य कार्रवाई की मंजूरी न दे या समय-सीमा न बढ़ा दे।

मुर्कोव्स्की ने कहा कि 1 मई को कांग्रेस को बताया गया था कि लड़ाई खत्म हो गई है। इसके बाद बातचीत जारी रहने के दौरान युद्धविराम बनाए रखने के लिए जून में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बाद में यह समझौता टूट गया और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास हमले फिर से शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने 10 जुलाई को कांग्रेस को युद्ध शक्तियों के बारे में एक नया नोटिफिकेशन भेजा, जिससे 60 दिनों की नई समय-सीमा शुरू हो गई। मुर्कोव्स्की ने कहा, 'मुझे इस प्रक्रिया को लेकर चिंता है, क्योंकि ऐसी स्थिति बन गई है जहां राष्ट्रपति को युद्ध शक्तियों की समय-सीमा को ठीक उसी समय खत्म करने की छूट मिल जाती है जब अस्थायी युद्धविराम की घोषणा के कारण यह कानूनी रूप से असुविधाजनक हो।' रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि पेंटागन व्हाइट हाउस के इस रुख से सहमत है कि राष्ट्रपति के पास ऑपरेशन जारी रखने के लिए पर्याप्त संवैधानिक अधिकार हैं।

हूतियों की नई धमकीः सऊदी बंदरगाहों से कारोबार करने वाले जहाज बन सकते हैं निशाना

एजेंसी

सना। यमन के हूती विद्रोहियों ने अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि जो जहाज सऊदी अरब के बंदरगाहों के साथ कारोबार करेंगे, वे सैन्य कार्रवाई का निशाना बन सकते हैं। यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब हूतियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान किया है, जिसे हालात में एक नए तनाव के रूप में देखा जा रहा है। यमन की राजधानी सना में मौजूद हूती समूह के 'ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस कोऑर्डिनेशन सेंटर' की ओर से भेजे गए एक ईमेल में कहा गया है कि यह चेतावनी सिर्फ सऊदी झंडे वाले जहाजों के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी जहाजों पर भी लागू होगी जो सऊदी बंदरगाहों पर सामान लादते या उतारते हैं। इटली की समाचार एजेंसी एडनक्रोनोस की जानकारी के अनुसार, ईमेल में शिपिंग कंपनियों से कहा गया है कि वे सऊदी बंदरगाहों से जुड़े किसी भी सफर की योजना बनाते समय पूरी सावधानी बरतें। चेतावनी दी गई है कि ऐसे कारोबारी कामों में शामिल जहाज हूतियों की मारक क्षमता के दायरे में आने पर हमले का निशाना बन सकते हैं। यह चेतावनी हूतियों की ओर से सऊदी जहाजों के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद आई। कुवैत और कतर समेत कई क्षेत्रीय देशों ने हूतियों के इस कदम को खारिज किया और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत समुद्री आवाजाही की आजादी का समर्थन दोहराया।

भारत दुनिया की सबसे प्रभावशाली आवाजों में शामिल : नॉर्थ मैसेडोनिया की राष्ट्रपति

स्कोप्जे। नॉर्थ मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्यानोव्स्का-दावकोवा ने भारत की सभ्यतागत विरासत और दुनिया में उसकी बढ़ती अहमियत की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लंबे समय से चली आ रही सभ्यताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि आज भारत आर्थिक विकास, तकनीकी नवाचार और वैज्ञानिक उपलब्धियों में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और वैश्विक स्तर पर सबसे प्रभावशाली आवाजों में शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नॉर्थ मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्यानोव्स्का-दावकोवा ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत बेहद सौहार्दपूर्ण, खुली और भविष्य पर केंद्रित रही। भारत और नॉर्थ मैसेडोनिया के रिश्तों में अभी भी आगे बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, 'आज हमारी बातचीत बेहद सौहार्दपूर्ण, खुली और भविष्य को ध्यान में रखकर हुई। हमने अपने अच्छे राजनीतिक संबंधों की पुष्टि की और इस बात पर सहमति जताई कि दोनों देशों के रिश्तों में अभी बहुत संभावनाएं हैं।

नूरिस्तान में भीषण बाढ़ से 20 लोगों की मौत और 80 घायल, 100 लापता

काबुल। अफगानिस्तान के नूरिस्तान प्रांत स्थित पारून शहर में आई भीषण बाढ़ से 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 80 से अधिक लोग घायल हुए हैं। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी। तालिबान अधिकारियों के एक बयान का हवाला देते हुए अफगानिस्तान की समाचार एजेंसी खामा प्रेस ने बताया कि पारून और आसपास के इलाकों में आई बाढ़ के बाद अभी भी 100 से अधिक लोग लापता हैं। तालिबान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि नूरिस्तान के पारून और कई अन्य क्षेत्रों में भारी बाढ़ ने व्यापक नुकसान पहुंचाया है। इस आपदा की जद में बड़ी संख्या में लोग आए और संपत्ति को भारी हानि हुई है। प्राधिकरण के सूचना एवं प्रकाशन प्रमुख और प्रवक्ता हाफिज मोहम्मद यूसुफ हमद ने बताया कि स्थिति का आकलन करने, लापता लोगों की तलाश करने और नुकसान का पता लगाने के लिए विशेष टीमें प्रभावित इलाकों में भेजी गई हैं। बाढ़ के कारण कई आवासीय घर, कृषि भूमि और दुकानें क्षतिग्रस्त या पूरी तरह नष्ट हो गई हैं, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। हमद ने कहा कि बचाव और खोज अभियान जारी रहने के कारण मृतकों और घायलों की संख्या में बदलाव हो सकता है।

नेपाल में बागमती सरकार से यूएमएल के छह मंत्रियों का सामूहिक इस्तीफा

काठमांडू। नेपाल की बागमती प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। केंद्र में सत्ता समीकरण बदलने के बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) यानी सीपीएन-यूएमएल के सभी छह मंत्रियों ने प्रदेश सरकार से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। मंत्रियों ने एक साथ अपने इस्तीफे इन्द्र बहादुर बनियां को सौंपे। इस्तीफा देने वालों में कृषि एवं पशुपालन मंत्री मधुसूदन पौडेल, भौतिक अवसंरचना विकास मंत्री डॉ. दिनेश चन्द्र देवकोटा, उद्योग, पर्यटन, श्रम एवं परिवहन मंत्री जयराम थापा, वन एवं पर्यावरण मंत्री भरत बहादुर केसी, स्वास्थ्य मंत्री किरण थापा तथा उद्योग, वाणिज्य, भूमि एवं प्रशासन मंत्री बिन्दु श्रेष्ठ शामिल हैं। सभी मंत्री काठमांडू से लौटने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे और अपना इस्तीफा सौंपा । यूएमएल ने सरकार से अपना समर्थन भी वापस ले लिया । इसके बाद मुख्यमंत्री इन्द्र बहादुर बनियां के नेतृत्व वाली सरकार विधानसभा में अल्पमत में आ गई है, जिससे सरकार के भविष्य पर राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ गई है। बागमती में सरकार का गठन नेपाली कांग्रेस और यूएमएल के गठबंधन से हुआ था, जिसमें नेपाली कांग्रेस की ओर से इन्द्र बहादुर बनियां को मुख्यमंत्री बनाया गया था।

रिसर्च और डेवलपमेंट की रेस में अमेरिका के बराबर पहुंचा चीन : व्हाइट हाउस रिपोर्ट

एजेंसी

वॉशिंगटन । व्हाइट हाउस ने विज्ञान नीति पर एक बड़ी रिपोर्ट में कहा है कि रिसर्च पर खर्च के मामले में चीन अमेरिका का बराबरी का कॉम्पिटिटर बन गया है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि बीजिंग की सुनियोजित कोशिशों से अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी में उसकी क्षमताएं तेजी से बढ़ रही हैं। यह आकलन 'साइंसः ए न्यू गोल्डन एज' में किया गया है। इसे व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी ने जारी किया था। यह अमेरिका के सालाना लगभग 200 अरब डॉलर के फेडरल रिसर्च और डेवलपमेंट सिस्टम को फिर से व्यवस्थित करने का एक ब्लूप्रिंट है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले बीस सालों में, चीन का रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च, जो पहले अमेरिका के मुकाबले न के बराबर था, कुछ पैमानों के अनुसार 'परचेजिंग-पावर-एडजस्टेड' आधार पर अब अमेरिका के बराबर हो गया है। इसमें इस कॉम्पिटिशन की तुलना कोल्ड वॉर (शीत युद्ध) के दौर से की गई है। रिपोर्ट में अमेरिका, चीन और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ

की तुलना करने वाले एक चार्ट में कहा गया है, 'पहली बार, अमेरिका को रिसर्च और डेवलपमेंट खर्च में 'परचेजिंग पावर पैरिटी' (पीपीपी)-एडजस्टेड आधार पर बराबरी का कॉम्पिटिटर मिला है।' दस्तावेज़ में कहा गया है कि बीजिंग ने वैज्ञानिक रिसर्च क्षमता को अपनी ग्लोबल कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी के केंद्र में रखा है, जिसमें सबसे ऊंचे स्तर पर फैसले लिए जाते हैं और अलग-अलग सेक्टर में रिसर्च की कोशिशों में तालमेल बिठाया जाता है। इसमें कहा गया है, 'समाज के सभी वर्गों को शामिल करने वाले इस नजरिए की वजह से चीन बुनियादी वैज्ञानिक रिसर्च के लिए संसाधन जुटा पाया है, राष्ट्रीय हित की अहम टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ पाया है और अपनी इनोवेशन प्रक्रिया में सुधार कर पाया है।' चीन की पहचान ऑटोनॉमस वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं (खुद काम करने वाली लैब) में भी एक कॉम्पिटिटर के तौर पर की गई है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स प्रयोगों को डिजाइन करने और उन्हें करने में मदद कर सकते हैं।

अमेरिका ने ईरान युद्ध का खर्च 37.5 अरब डॉलर बताया

एजेंसी

वॉशिंगटन । अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सीनेटरों को बताया कि ईरान के साथ जारी युद्ध में अब तक अनुमानित 37.5 अरब डॉलर का खर्च आया है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने होर्मुज जलडमरूमध्य में फिर से शुरू हुई लड़ाई के बीच लगभग 88 अरब डॉलर की आपातकालीन फंडिंग की मांग की है। हेगसेथ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अतिरिक्त फंडिंग की मांग पर सीनेट की एप्रोप्रिएशन कमेटी की सुनवाई के दौरान यह आंकड़ा बताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन 87.6 अरब डॉलर की मांग कर रहा है, जिसमें सेना के लिए लगभग 67 अरब डॉलर शामिल हैं। डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड डर्बिन के सवालों के जवाब में हेगसेथ ने कहा, 'आज हमारे पास जो अनुमान है, वह 37.5 अरब डॉलर है। उन्होंने कहा कि इस अनुमान में अब तक हुए कुछ खर्च और 30 सितंबर तक सेना के वेतन, ऑपरेशन और रखरखाव के संभावित खर्च शामिल हैं।

इस मांग से सेना की तैयारी के लिए 21 अरब डॉलर मिलेंगे, जिसमें वेतन, उपकरण बदलना, आगे तैनात सेना, ईंधन और नेशनल गार्ड का सहयोग शामिल है। इसके अलावा, 46 अरब डॉलर से गोला-बारूद का उत्पादन बढ़ेगा और हाइपरसोनिक हथियारों, काउंटर-ड्रोन सिस्टम, सैटेलाइट और अन्य क्षमताओं में निवेश में तेजी आएगी।

हेगसेथ ने कहा कि अगर कांग्रेस अतिरिक्त फंड को मंजूरी नहीं देती है, तो ट्रेनिंग एक्सरसाइज में कटौती करनी पड़ सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि सेना को सालों से रुकी हुई मेंटेनेंस और हथियारों के कम होते स्टॉक जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।उन्होंने कहा, 'इन फंड के बिना, हमें गंभीर कमियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे हमारे सर्विस मेंबर्स को सैलरी देने, तेजी से उपकरण और गोला-बारूद की भरपाई करने और बिना किसी रुकावट के जरूरी ऑपरेशन जारी रखने की हमारी क्षमता पर खतरा पैदा हो सकता है।' डेमोक्रेट्स ने सवाल किया कि पेंटागन को और पैसे की जरूरत क्यों है, जबकि उसके पास पहले के खर्च पैकेज से लगभग 75 बिलियन डॉलर का बिना इस्तेमाल हुआ फंड अभी भी मौजूद है। सीनेटर पैटी मरे ने कहा कि सप्लीमेंटल फंड में यूएस सदर्न कमांड के लिए लगभग 1 बिलियन डॉलर, वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड की तैनाती जारी रखने के लिए लगभग 1 बिलियन डॉलर और दक्षिणी सीमा पर ऑपरेशन के लिए 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की राशि शामिल है। मरे ने कहा, 'अमेरिकी जनता इस युद्ध का जल्द और रणनीतिक अंत चाहती है, न कि अपने टैक्स के 70 बिलियन डॉलर इसे जारी रखने में खर्च होते देखना चाहती है।' इस सुनवाई में मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखने के लिए प्रशासन के कानूनी अधिकार को लेकर भी तीखे मतभेद सामने आए।

जयशंकर ने फिलीपींस की विदेश मंत्री लाजारो से हिंद-प्रशांत पर की अहम चर्चा

एजेंसी

मनीला । विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को मनीला में फिलीपींस की विदेश मंत्री थेरेसा पी. लाजारो से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत-फिलीपींस रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के हालिया घटनाक्रमों की समीक्षा की। बैठक के बाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, 'आज मनीला में फिलीपींस की विदेश मंत्री थेरेसा पी. लाजारो से मिलकर खुशी हुई। व्यापार एवं निवेश, शिक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, समुद्री सहयोग, क्षमता निर्माण और विकास सहयोग पर केंद्रित हमारी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर सार्थक चर्चा हुई।' उन्होंने आगे कहा, 'हमने हिंद-प्रशांत क्षेत्र के हालिया घटनाक्रमों पर भी विचार-विमर्श किया।' वहीं, फिलीपींस की विदेश मंत्री लाजारो ने भी एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच

रणनीतिक साझेदारी पर 'सार्थक चर्चा' हुई। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों ने फिनटेक, व्यापार एवं निवेश, उच्च शिक्षा, दवा उद्योग, रक्षा, समुद्री सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

यह बैठक ऐसे समय हुई है, जब हाल ही में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में फिलीपींस और चीन के बीच तनाव बढ़ा है। फिलीपींस के अनुसार, 20 जुलाई को दक्षिण चीन सागर के सेकंड थॉमस शोल क्षेत्र में चीन ने उसकी नौसेना के जवानों के खिलाफ 'खतरनाक और आक्रामक कार्रवाई' की। भारत के लिए दक्षिण चीन सागर के घटनाक्रम रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। भारत का एक बड़ा व्यापार हिंद-प्रशांत क्षेत्र के समुद्री मार्गों से होकर गुजरता है। नई दिल्ली लगातार नौवहन की स्वतंत्रता, निर्बाध समुद्री व्यापार और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता रहा है।

हाल ही में भारत ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत नौवहन, हवाई आवाजाही और वैध समुद्री व्यापार की स्वतंत्रता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि दक्षिण चीन सागर से जुड़े सभी विवादों का समाधान संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) के तहत शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए।

इस बीच, अमेरिका के नेतृत्व में 12 देशों ने दक्षिण चीन सागर पर वर्ष 2016 के ऐतिहासिक मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसले की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर 'स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत' के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस फैसले में चीन के व्यापक समुद्री दावों को खारिज किया गया था। संयुक्त बयान में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एस्टोनिया, जापान, लातविया, लिथुआनिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, रोमानिया, स्लोवेनिया और यूनाइटेड किंगडम ने अंतरराष्ट्रीय कानून पर आधारित शांतिपूर्ण, स्थिर और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के समर्थन की बात दोहराई।

अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ लगातार 11वीं रात हमले किए : सेंटकॉम

एजेंसी

वाशिंगटन । अमेरिकी सेना ने (अमेरिकी समय) शाम 8:15 बजे ईरान पर लगातार 11वीं रात सैन्य हमले किए। इसकी जानकारी अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। सेंटकॉम के मुताबिक, इन हमलों में ईरान के सैन्य ऑपरेशन सेंटर, समुद्री सैन्य क्षमताओं से जुड़े ठिकाने, सैन्य विमानों के हैंगर, ड्रोन स्टोरेज सुविधाओं और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना है, जिससे वह होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों के लिए खतरा पैदा कर सके। सेंटकॉम ने दावा किया कि पिछले तीन महीनों में ईरान ने इस अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग से गुजर रहे 30 से अधिक व्यावसायिक जहाजों पर हमले किए हैं। अमेरिका के अनुसार, इन हमलों से सैकड़ों नाविकों की जान खतरे में पड़ी और समुद्र में स्वतंत्र आवाजाही भी प्रभावित हुई।

हालांकि, अमेरिका का कहना है कि इन घटनाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरूमध्य अभी भी व्यापारिक जहाजों के लिए खुला हुआ है। सेंटकॉम के मुताबिक, मई की शुरुआत से अब तक उसकी सेना ने इस समुद्री मार्ग से करीब 900 व्यावसायिक जहाजों के सुरक्षित आवागमन में मदद की है। इन जहाजों में लगभग 450 मिलियन बैरल कच्चा तेल ले जाया गया। इससे पहले भी सेंटकॉम ने बताया था कि उसकी सेना ने लगातार 11वीं रात ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू किए हैं। अमेरिका का कहना है कि इन कार्रवाईयों का उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान से पैदा होने वाले खतरे को कम करना है।

वहीं, दूसरी ओर ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के ताजा हमलों के जवाब में बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों, संसाधनों और अन्य सैन्य ढांचे पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है।

ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ अहम परमाणु समझौते को मंजूरी दीः रिपोर्ट

एजेंसी

वॉशिंगटन । 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट दी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक अहम परमाणु समझौते को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। इस समझौते के तहत सऊदी अरब में यूरेनियम संवर्धन की अनुमति मिल सकती है और अमेरिकी कंपनियों के लिए अरबों डॉलर की कमाई हो सकती है। इस 30 साल के समझौते से सऊदी अरब को एक सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम तक पहुंच मिल जाएगी। 'द जर्नल' के अनुसार, समझौते को इस तरह से तैयार किया गया है कि अमेरिकी कंपनियां सऊदी अरब के उभरते हुए न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर के केंद्र में रहें और विदेशी कंपनियां इससे बाहर रहें। यह डील वॉशिंगटन और रियाद के बीच न्यूक्लियर सहयोग के बड़े विस्तार का संकेत हो सकती है। इससे मिडिल ईस्ट में संवेदनशील न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के प्रसार को लेकर कांग्रेस में चिंताएं फिर से बढ़ सकती हैं। एक अहम प्रावधान के

तहत, अमेरिकी कंपनियां सऊदी अरब में यूरेनियम एनरिचमेंट (संवर्धन) प्लांट बना सकती हैं। 'जर्नल' के अनुसार, यह प्रोजेक्ट तभी आगे बढ़ेगा जब अमेरिका और सऊदी अरब की संयुक्त स्टडी में यह नतीजा निकले कि ऐसे प्लांट की जरूरत है। यूरेनियम एनरिचमेंट से आम नागरिकों के इस्तेमाल वाले न्यूक्लियर रिएक्टरों के लिए ईंधन बनाया जा सकता है। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, अगर बहुत ऊंचे स्तर पर किया जाए तो न्यूक्लियर हथियारों के लिए भी सामग्री बनाई जा सकती है। दोहरे इस्तेमाल की इसी क्षमता की वजह से एनरिचमेंट लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय न्यूक्लियर बातचीत के सबसे संवेदनशील हिस्सों में से एक रहा है। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि सीधे अमेरिकी दखल से सऊदी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर वॉशिंगटन का असर बढ़ेगा। तर्क है कि अमेरिका की भागीदारी से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सैन्य मकसद के लिए इस्तेमाल होने से रोकने में भी मदद मिलेगी।

अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने पिछले हफ्ते के आखिर में इस समझौते को मंजूरी दे दी थी। उम्मीद है कि अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट और सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुलअजीज बिन सलमान बुधवार को इस पर हस्ताक्षर करेंगे।

राइट ने अप्रैल 2025 में इस क्षेत्र की अपनी पहली विदेश यात्रा के दौरान अपने सऊदी समकक्ष के साथ प्रस्तावित सहयोग पर चर्चा की थी। इस समझौते से रिएक्टर बनाने, परमाणु ईंधन सेवाएं देने और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे के काम में लगी अमेरिकी कंपनियों को बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। सऊदी अरब तेल के अलावा अपने ऊर्जा स्रोतों और अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की कोशिश के तहत नागरिक परमाणु ऊर्जा विकसित करना चाहता है। सऊदी अरब का यह भी तर्क है कि परमाणु ऊर्जा से देश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने और निर्यात के लिए अधिक तेल बचाने में मदद मिल सकती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेनेरिक दवाओं पर चरणबद्ध टैरिफ की घोषणा की

एजेंसी

वॉशिंगटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दवा प्रोडक्शन को यूनाइटेड स्टेट्स में शिफ्ट करने के लिए चरणबद्ध टैरिफ की घोषणा की है। उन्होंने घोषणा की कि इम्पोर्टेड जेनेरिक दवाएं 1 अगस्त, 2026 से दो साल तक टैरिफ से मुक्त रहेंगी। इसके बाद उन पर 100 प्रतिशत और बाद में 200 प्रतिशत ड्यूटी लगेगी। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया, '1 अगस्त, 2026 से, अमेरिका में लाई जाने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर दो साल के लिए जीरो परसेंट टैरिफ लागू रहेगा, जिसके बाद एक साल के लिए टैरिफ को बढ़ाकर 100 प्रतिशत और उसके बाद 200 प्रतिशत कर दिया जाएगा।' उनकी इस नीति से अमेरिकता में जेनेरिक दवाएं सप्लाई करने वालों पर बड़ा असर पड़ेगा। ट्रंप के बयान में किसी देश या कंपनी का नाम नहीं लिया गया और न ही इस बारे में कोई जानकारी दी गई कि टैरिफ सिस्टम को कैसे मैनेज किया जाएगा। इसमें यह भी नहीं बताया गया कि दो साल के समय में प्लांट बनाने वाली कंपनियां छूट के लिए क्वालिफाई करेंगी या ज्यादा ड्यूटी लागू होने से पहले उन्हें प्रोडक्शन शुरू करना होगा। ट्रंप ने कहा कि फेज्ड टैरिफ स्ट्रक्चर का मकसद दवा बनाने वालों को अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इन्वेस्ट करने के लिए बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा, 'यह अमेरिका में जेनेरिक फार्मास्युटिकल प्रोडक्शन को फिर से शुरू करने के लिए किया गया है, जिसमें उन कंपनियों पर पेनल्टी लगाई जाएगी जो उन्हें दिए गए समय के अंदर प्लांट और इक्विपमेंट नहीं बनाने का फैसला करती हैं।' ट्रंप ने कहा, 'इस पॉलिसी का मकसद यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों की सुरक्षा करना है।' राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से घोषित टाइमलाइन के तहत, जेनेरिक दवा का इंपोर्ट 1 अगस्त के बाद दो साल तक बिना किसी टैरिफ के अमेरिका में आता रहेगा। इसके बाद उन पर एक साल के लिए 100 परसेंट टैरिफ लगेगा, जिसके बाद 200 परसेंट ड्यूटी लगेगी। ट्रंप ने जेनेरिक दवाओं के लिए नए टाइमटेबल को अपने एडमिनिस्ट्रेशन के पेटेंटेड और ब्रांडेड दवाओं के ट्रीटमेंट से अलग बताया। राष्ट्रपति ने घोषणा में उस पॉलिसी के बारे में और जानकारी दिए बिना कहा, 'पेटेंटेड, ब्रांडेड, या इनोवेटिव दवाओं पर पॉलिसी, जो इतनी सफल रही है, वैसी ही रहेगी।'

नेपाल में मौसम खराब, आज भी अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग बंद

एजेंसी

काठमांडू। नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण विभिन्न हिस्सों में बाढ़ और भू-स्खलन से स्थिति खराब हो गई है। इसके चलते कई प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क मार्ग बंद हैं। नेपाल पुलिस ने यात्रियों से सतर्कता बरतने और यात्रा से पहले सड़क की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। बारिश के कारण बीपी राजमार्ग पर काभ्रेपलाञ्चोक और सिंधुली को जोड़ने वाले खुर्कोट-नेपालथोक-कटुन्जेबेसी खंड में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एहतियात के तौर पर इस मार्ग पर शाम 6 बजे से सुबह 4 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही अगले आदेश तक रोक दी गई है। इसी तरह कांति लोकपथ पर मकवानपुर खंड में शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक यातायात प्रतिबंधित कर दिया गया है। मेची राजमार्ग के इलाम नगरपालिका स्थित राजदुवाली क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई है। इससे यह मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। वहीं, अरनिको राजमार्ग पर सिंधुपालचोक जिले के भोटेकोशी के जिरोकिलो और कोदारी क्षेत्र में भू-स्खलन होने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। बागलुङ जिले में जैमिनी नगरपालिका के बेलबगर स्थित कालीगण्डकी कॉरिडोर भी भूस्खलन के कारण पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। इसके अलावा, पांचथर जिले के मिक्लाजुङ ग्रामीण नगरपालिका के कोप्चे क्षेत्र में राँके-राबी-भेडेटार सड़क, तथा गोरखा जिले के धार्चे के लिडिङ क्षेत्र में आरुघाट-मच्छीखोला सड़क भी भूस्खलन और खराब मौसम से प्रभावित हुई है।

भारत-चीन रिश्तों में सकारात्मक प्रगति, मनीला में जयशंकर ने वांग यी से की व्यापक बातचीत

एजेंसी

मनीला । विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने फिलीपींस की राजधानी मनीला में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ व्यापक बातचीत की। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री ने कहा, 'भारत और चीन के संबंध धीरे-धीरे सामान्य होने की दिशा में बढ़े हैं।' दोनों ने भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों, सीमा पर शांति एवं स्थिरता के साथ ही प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बैठक की जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) और आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) की बैठक के इतर चीन के विदेश मंत्री एवं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की पोलित ब्यूरो के सदस्य वांग यी के साथ विस्तृत बातचीत की। बैठक की शुरुआत में अपने संबोधन में जयशंकर ने कहा, 'आपसे फिर मिलकर खुशी हुई। ईएएस और आसियान क्षेत्रीय मंच में हमारी भागीदारी न केवल सामूहिक रूप से विचारों के आदान-प्रदान का अवसर देती है, बल्कि इस द्विपक्षीय बैठक का भी अवसर प्रदान करती है।' उन्होंने कहा कि यह बैठक भारत-चीन संबंधों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर है। उन्होंने कहा, 'हम एक वर्ष पहले मिले थे और आप हाल ही में भारत भी आए थे। आज की यह बैठक हमारे संबंधों का आकलन करने और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय एवं वैश्विक घटनाक्रमों पर विचार-विमर्श के लिए उपयोगी होगी। विदेश मंत्री ने कहा कि अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक के बाद दोनों देशों के संबंध धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा, 'अक्टूबर 2024 में कजान में हमारे नेताओं की बैठक के बाद भारत और चीन के संबंध धीरे-धीरे सामान्य होने की दिशा में बढ़े हैं। पिछले अगस्त में तियानजिन में उनकी मुलाकात ने इस दिशा को और मजबूत किया।' जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर संबंध आपसी सम्मान, साझा हितों और एक-दूसरे की संवेदनशीलताओं के सम्मान पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने कहा, 'ऐसे संबंध बहुध्रुवीय एशिया और बहुध्रुवीय विश्व के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।' सीमा विवाद पर विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता सामान्य द्विपक्षीय संबंधों के लिए अनिवार्य शर्त है। उन्होंने कहा, 'सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता सामान्य संबंधों की पूर्वशर्त है। अक्टूबर 2024 से दोनों पक्ष इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस पर आगे भी निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता होगी।' जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच मतभेदों को विवाद में नहीं बदलने देना चाहिए। उन्होंने कहा, 'हमारे नेताओं ने सहमति जताई थी कि मतभेद विवाद का रूप न लें। इन्हें उचित ढंग से संभालना कूटनीति की जिम्मेदारी है।' विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों का स्वागत किया। उन्होंने प्रत्यक्ष उड़ानों की बहाली, वीजा व्यवस्था में सुधार, कैलाश मानसरोवर यात्रा के दोबारा शुरू होने और सीमा व्यापार की बहाली जैसे कदमों का उल्लेख किया। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी भी कई मुद्दों पर काम किया जाना बाकी है। इनमें भारतीय कंपनियों के लिए निष्पक्ष बाजार पहुंच, व्यापार असंतुलन, आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी चिंताएं तथा सरकारी और जन-स्तर पर संपर्क को और सुगम बनाना शामिल है। जयशंकर ने ब्रिक्स की भारत की अध्यक्षता के दौरान चीन द्वारा दिए गए सहयोग की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में दोनों देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय महत्व के प्रमुख मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करना पहले से कहीं अधिक आवश्यक है।

page 1 and 8 July 23_page 1 Mar 25 final ds.qxd 7/23/2026 12:49 AM Page 2

करें सभी इंतजाम, जलभराव की समस्या बर्दाश्त नहीं : मुख्यमंत्री

गोरखपुर के विकास कार्यों, बाढ़ बचाव और जलनिकासी की तैयारियों की समीक्षा में सीएम योगी ने दी चेतावनी*

गोरखपुर, 22 जुलाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को चेतावनी है कि महानगर में किसी भी दशा में जलभराव की समस्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि नाले, नालियों की बड़े पैमाने पर सफाई कराने और बारिश होने पर अधिकाधिक पंपों का संचालन सुनिश्चित करते हुए ध्यान रखा जाए कि कहीं भी जलभराव न होने पाए। जलभराव की समस्या के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता पाए जाने पर जवाबदेही तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सीएम योगी बुधवार दोपहर एनेक्सी भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के विकास कार्यों, बाढ़ बचाव और जलनिकासी की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उनका सर्वाधिक जोर जलनिकासी को लेकर रहा। उन्होंने दो टूक कहा-'जो भी जरूरी तैयारी या व्यवस्थाएं करनी हैं, उन्हें सुनिश्चित किया जाए, कहीं भी और किसी भी दशा में जलभराव नहीं दिखना चाहिए।' मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी

नाले, नालियों की नियमित सफाई कराकर उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोका जाए ताकि इससे नाले चोक न होने पाएं। मुख्यमंत्री ने समझाया कि हमें मौसम के प्रभाव के अनुसार खुद को तैयार रखना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाला निर्माण और मरम्मत के प्रस्ताव समय से लेकर समयबद्ध तरीके से काम पूरा किया जाए। सभी अधिकारी, कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें और कहीं भी नकारात्मक वातावरण न बनने दें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महानगर के राप्ती कॉम्प्लेक्स, गोरक्ष एंक्लेव, विजय चौराहा तथा धर्मशाला आदि पर हुए जलभराव की जानकारी ली और कहा कि नालों की नियमित रूप से सफाई के बाद उन्हें ढका जाए।

नगर निगम के सभी पंप पूरी क्षमता से संचालित किए जाएं। उन्होने कहा कि इन व्यवस्थाओं के साथ ही लोगों को प्रेरित किया जाए कि वह कूड़ा नालियों में न डालें। स्वच्छता के लिए कार्यक्रम चलाया जाए, साथ ही नियमित छिड़काव एवं फागिंग कराई जाए। सीएम ने कहा कि स्वच्छता के कार्यक्रम में अधिकाधिक जनसहभगिता भी सुनिश्चित होनी चाहिए। टीम बना कर हर वार्ड, मलिन बस्तियों, खाली प्लाटों की सफाई कराई जाए और कूड़ा निस्तारण सही से किया जाए।

सीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता अभियान चलाया जाए और इसे रूटीन के कार्यों का हिस्सा बनाया जाए।

किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर तय होगी जवाबदेही, करेंगे कड़ी कार्रवाई - सीएम योगी

***पूरी जिम्मेदारी से कार्य करें अधिकारी व कमर्चारी, कहीं भी नकारात्मक वातावरण न बनने दें - सीएम**

स्वच्छता के कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाए। शासकीय भवनों में भी सफाई पर ध्यान दिया जाए। उन्होने स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित करने, स्ट्रीट लाइटों को ठीक रखने और सभी सीसीटीवी को अद्यतन रखने के भी निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बेसहारा गोवंश सडको पर न रहें। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया कि डॉग सड़कों पर न रहें। उनके लिये डॉग शेल्टर बनाया जाए। सीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि जिला अस्पताल सहित सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त संख्या मे एंटी स्नैक वेनम और एंटी रैबीज वैक्सीन उपलब्ध रहे।

बाढ़ से बचाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी तैयारियां पूर्ण रहनी चाहिए। तटबंधों की सुरक्षा के लिए नियमित पैट्रोलिंग हो। बाढ़ चौकियां सक्रिय रहें और बाढ़ राहत केंद्रों पर व्यवस्था अच्छी रहे। उन्होने कहा कि बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों में बीमारियों से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरती जाएं। सड़कें क्षतिग्रस्त न रहने पाएं।

स्थानीय समाचार

एनसी जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को सिर्फ राज्य के दर्जे तक सीमित करके 2019 के बाद के बदलावों को सामान्य बना रही है : महबूबा मुफ्ती

श्रीनगर, 22 जुलाई (हि.स.)। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा कि सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक विमर्श को सिर्फ राज्य के दर्जे की मांग तक सीमित करके 5 अगस्त, 2019 के संवैधानिक बदलावों को सामान्य बना रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को इस मुद्दे पर केंद्र से संपर्क करने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी। श्रीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए महबूबा ने कहा कि जनता का जनादेश सिर्फ राज्य के दर्जे की बहाली तक सीमित नहीं है बल्कि जम्मू-कश्मीर के सामने मौजूद व्यापक राजनीतिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए भी है। जनता का जनादेश केवल राज्य का दर्जा पाने के लिए नहीं है। यह व्यापक राजनीतिक मुद्दों के समाधान के लिए भी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी ताकि जम्मू-कश्मीर की एकजुट आवाज केंद्र के समक्ष रखी जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केवल राज्य के दर्जे पर ध्यान केंद्रित करके और अनुच्छेद 370 तथा अन्य संवैधानिक सुरक्षा उपायों से संबंधित अपने वादों से पीछे हटकर नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 अगस्त, 2019 की घटनाओं को सामान्य बनाने में मदद कर रही है। उन्होंने अनुच्छेद 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर अब पार्टी का मानना है कि इसे हासिल नहीं किया जा सकता तो उसने इसे अपने चुनाव घोषणापत्र में क्यों शामिल किया था और विधानसभा चुनावों के दौरान इस मुद्दे को बार-बार क्यों उठाया था।

कठुआ में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक, 22 मामलों की समीक्षा

कठुआ, 22 जुलाई (हि.स.)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कठुआ के अध्यक्ष जतिंदर सिंह जम्वाल की अध्यक्षता में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की तीसरी बैठक आयोजित हुई जिसमें जिला जेल कठुआ में बंद 22 विचाराधीन कैदियों के मामलों की समीक्षा की गई।

बैठक में एडीसी कठुआ महिमा मदान, एएसपी कठुआ सुनील केसर, जेल अधीक्षक मोहम्मद हुसैन, डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल मोहितर पाल व सुमित जसरोटिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का संचालन सचिव डीएलएसए उर्वशी आर. भार्गव ने किया। बैठक में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और भारत का

सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के तहत मामलों की समीक्षा कर पात्र कैदियों को अनावश्यक देरी से बचाने पर जोर दिया गया। विचार-विमर्श के बाद संबंधित मामलों में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। अध्यक्ष ने कहा कि यह समिति विचाराधीन कैदियों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा और समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। बैठक का समापन सभी विभागों के समन्वय से त्वरित कार्रवाई और मामलों के निष्पक्ष निस्तारण के संकल्प के साथ हुआ।

उपायुक्त रामबन ने भारी बारिश के बाद बहाली कार्यों, आवश्यक सेवाओं और आपदा तैयारियों की समीक्षा की

रामबन, 22 जुलाई। उपायुक्त रामबन मोहम्मद इलियास खान ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर भारी बारिश के बाद बहाली कार्यों की प्रगति, आवश्यक सेवाओं एवं जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता तथा मौसम संबंधी आपात स्थितियों से निपटने के लिए विभिन्न विभागों की तैयारियों का जायजा लिया।

उपायुक्त ने विभागों के बीच बेहतर समन्वय, आवश्यक सेवाओं की शीघ्र बहाली तथा फील्ड स्तर पर लगातार निगरानी पर जोर देते हुए कहा कि मानसून के दौरान आम जनता की परेशानी कम करने और जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें। बहाली कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को निर्देश दिए कि नाशरी से बनिहाल तक राष्ट्रीय राजमार्ग-44 को यातायात योग्य बनाए रखा जाए। इसके लिए संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त मशीनरी और कर्मचारियों की तैनाती कर भूस्खलन, मलबा और कीचड़ को तत्काल हटाया जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) तथा सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों पर यातायात शीघ्र बहाल करने तथा किसी भी व्यवधान की स्थिति से निपटने के लिए मशीनरी और कर्मचारियों को पूरी तरह तैयार रखने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने मागम और बीरवाह अस्पतालों का दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं का लिया जायजा, क्षतिग्रस्त डायवर्जन पुल पर बहाली कार्यों का किया निरीक्षण

बडगाम, 22 जुलाई। उपायुक्त बडगाम अथर आमिर खान ने आज मागम और बीरवाह के उप-जिला अस्पतालों (एसडीएच) का दौरा कर हालिया खराब मौसम के मद्देनजर स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की तथा निर्बाध चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

दौरे के दौरान उपायुक्त ने अस्पताल के वार्डों, उपचार सुविधाओं और मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों के सुचारु संचालन पर जोर देते हुए स्वास्थ्य विभाग को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए।

उन्होंने चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और मरीजों से भी बातचीत कर उपचार की गुणवत्ता तथा आवश्यक चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी ली।

बाद में उपायुक्त ने बीरवाह में सुखनाग नाले पर बने क्षतिग्रस्त डायवर्जन पुल के बहाली कार्यों का निरीक्षण किया, जहां यातायात जल्द बहाल करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को सभी क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि यातायात व्यवस्था जल्द सामान्य हो सके।

एसकेयूएएसटी-कश्मीर के कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरिकल्चर, मीरगुंड में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

श्रीनगर, 22 जुलाई। राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एसकेयूएएसटी-कश्मीर) के कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरिकल्चर, मीरगुंड की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई द्वारा विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने तथा स्वस्थ एवं नशामुक्त समाज के निर्माण के उद्देश्य से एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में संकाय सदस्यों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। वक्ताओं ने विशेष रूप से युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए इसके विरुद्ध सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्य वक्ता के रूप में एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. आबिद खालिक तंत्रे ने नशे की लत के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नशे की रोकथाम में शैक्षणिक संस्थानों, परिवारों और समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने विद्यार्थियों से जीवन में सही निर्णय लेने तथा नशे को कहें ना अभियान के प्रेरक बनने का आह्वान किया।

सहायक प्रोफेसर डॉ. इकराह अकबर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मानसिक स्वास्थ्य, स्वस्थ जीवनशैली और सकारात्मक मित्र मंडली के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने शैक्षणिक एवं व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने और नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने भी नशे की बढ़ती समस्या पर अपने विचार साझा किए और इससे निपटने के लिए जागरूकता, आत्मअनुशासन तथा सामुदायिक भागीदारी को आवश्यक बताया।

कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने नशामुक्त भारत के संकल्प को साकार करने तथा जागरूकता, जिम्मेदारी और सक्रिय नागरिकता के माध्यम से नशा मुक्त भारत अभियान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की सामूहिक शपथ ली।

उपायुक्त उधमपुर ने एनसीओआरडी बैठक की अध्यक्षता की, नशे के खिलाफ समन्वित कार्रवाई पर दिया जोर

उधमपुर, 22 जुलाई। उपायुक्त उधमपुर मिंगा शेरपा ने आज जिला स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) की बैठक की अध्यक्षता कर नशीले पदार्थों की रोकथाम संबंधी उपायों की समीक्षा की तथा मादक पदार्थ विरोधी अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए एनसीओआरडी तंत्र के पुनर्गठन पर चर्चा की। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त प्रेम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भट्ट तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में नशे की रोकथाम एवं नियंत्रण से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई, जिनमें नशा पीड़ितों की पहचान एवं पुनर्वास, पीआईटी-एनडीपीएस मामलों की प्रगति, नियमों का उल्लंघन करने वाली दवा दुकानों के विरुद्ध कार्रवाई, सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, मादक फसलों की अवैध खेती पर रोक, नशामुक्ति केंद्रों का निरीक्षण, ब्लॉकवार नशा प्रभावित व्यक्तियों का आंकड़ा, नशे के हॉटस्पॉट की पहचान, शैक्षणिक संस्थानों की निगरानी, सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) अभियान, जन-जागरूकता कार्यक्रम, दवा दुकानों में कम्प्यूटरीकृत बिलिंग प्रणाली, नशा मुक्ति पंचायतों की प्रगति तथा एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा शामिल रही। उपायुक्त ने संबंधित एजेंसियों को नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास तेज करने, नशा प्रभावित क्षेत्रों की कड़ी निगरानी रखने तथा समुदाय आधारित पुनर्वास और जन-जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को परामर्श सेवाएं मजबूत करने तथा विशेष रूप से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

सकीना इत्तू ने दक्षिण कश्मीर के जिलों का दौरा कर लगातार बारिश के बाद स्थिति की समीक्षा की

जिला मुख्यालयों में समीक्षा बैठकें कीं, बाढ़ संभावित क्षेत्रों में चौबीसों घंटे निगरानी के दिए निर्देश

श्रीनगर, 22 जुलाई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के निर्देश पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण तथा शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने आज दक्षिण कश्मीर के विभिन्न जिलों का दौरा कर लगातार हो रही बारिश के बाद उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया।

दौरे के दौरान मंत्री ने संबंधित उपायुक्तों तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिला मुख्यालयों में अलग-अलग समीक्षा बैठकें कर प्रतिकूल मौसम की स्थिति से निपटने के लिए की गई तैयारियों और राहत उपायों का आकलन किया।

मंत्री ने बाढ़ से निपटने की तैयारियों, आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र, आवश्यक सेवाओं की बहाली, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, सड़क संपर्क, बिजली एवं पेयजल आपूर्ति तथा आवश्यकता पड़ने पर राहत एवं निकासी व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की।

शोपियां में आपदा तैयारियों की समीक्षा

कुलगाम में मंत्री ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की तैयारियों की समीक्षा के लिए व्यापक बैठक की।

बैठक में विधायक देवसर पीरजादा फिरोज अहमद शाह, उपायुक्त कुलगाम शहजाद आलम, अतिरिक्त उपायुक्त कुलगाम विकार अहमद गिरी, सहायक आयुक्त राजस्व, सहायक आयुक्त विकास तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा किए गए बाढ़ सुरक्षा एवं शमन उपायों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखने तथा नदियों के जलस्तर की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने वेशो, वेथयात्रु तथा अन्य नालों के किनारे संवेदनशील स्थलों की शीघ्र पहचान कर वहां बाढ़ सुरक्षा उपाय मजबूत करने पर जोर दिया।

सकीना इत्तू ने जिले के निचले एवं संवेदनशील क्षेत्रों में तत्काल बाढ़ सुरक्षा कार्य शुरू करने के साथ-साथ दीर्घकालिक बाढ़ शमन योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए।

विधायक देवसर ने भी मौसम की स्थिति और बाढ़ से बचाव की तैयारियों को लेकर अपने सुझाव और महत्वपूर्ण टिप्पणियां प्रस्तुत कीं।

इससे पहले उपायुक्त कुलगाम और अतिरिक्त उपायुक्त ने जिले की तैयारियों पर विस्तृत प्रस्तुति देते हुए विभागवार रणनीति तथा राहत, बचाव एवं पुनर्वास तंत्र की जानकारी दी।

शोपियां में आवश्यक सेवाओं की समीक्षा

शोपियां में मंत्री ने मिनी सचिवालय में जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर मौसम की स्थिति तथा विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा की।बैठक में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, बिजली एवं पेयजल आपूर्ति, दवाओं और अन्य आपातकालीन सामग्री के भंडार की समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क रहने तथा आवश्यक सेवाएं निर्बाध बनाए रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने, आपसी समन्वय बनाए रखने तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित

कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने आम लोगों से भी अपील की कि वे प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी परामर्श का पालन करें, अनावश्यक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की यात्रा से बचें और प्रशासन का सहयोग करें।

बैठक में उपायुक्त शोपियां शिशिर गुप्ता, अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त डॉ. नासिर अहमद लोन, अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. जाकिर हुसैन फाज, मुख्य योजना अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जल शक्ति, केपीडीसीएल, सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता तथा राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, नगर निकाय, खाद्य, आपदा प्रबंधन एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

पुलवामा में बाढ़ तैयारियों का जायजा